the displaced person should be given an option to purchase the site occupied by him against payment in easy instalments of the value of the land assessed. The grant of these concessions did not preclude Government from exercising their own rights of ownership over the property in question."

One of the terms of the assurance was that in certain conditions, where the occupation is after 15th August, 1950, but before a certain other date, he would be entitled to take the land on a no-profit-no-loss basis or at its face value.

15 hrs.

That is the assurance. That shall be at the discretion of the Government. There will be no legal validity to this assurance. I beg to the hon. Deputy Minister to consider whether the assurance which he has given is a pious wish that has been expressed in the Report of the Select Committee on this Bill or that the assurance that he has given today on the floor of this House has got any legal value, when it has not been incorporated in this Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Would the hon Member like to continue and finish in another two minutes?

Shri Ajit Singh Sarhadi: No. I would like to continue.

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow. Now the two-hour discussion will start

---

15.01 hrs.

INDO-PAKISTAN CANAL WATER DISPUTE

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल पाकिस्तान की असेम्बली में नहरी पानी के विषय में एक विवाद हुआ। आज उस विषय पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में विवाद हो रहा है। लेकिन दोनों के नुक्ते-नजर में फर्क है। वहां पर दौलताना साहब ने भाषण देते हुये कहा :

"Over Kashmir and canal waters we will fight India with our own army. We will fight with our Police, our men and women and children will fight. We shall fight and fight and fight."

इसके बाद दौलताना साहब से ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से सवाल किया गया कि आपने दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किये थे मई ४, १९४८ को, तो दौलताना साहब कहते हैं

"The agreement relates to the waters of two canals. It was signed under duress."

हो सकता है कि चूंकि दौलताना साहब हिन्दुस्तान के खिलाफ हैं इसलिये उन्होंने यह बात कही हो। लेकिन इस समझौते पर दो आदमियों के और दस्तखत हैं जिनमें एक तो गुलाम मोहम्मद साहब थे, जो कि बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुये, और दूसरे शौकत हयात खां साहब थे। इन दोनों के भी हस्ताक्षर उस समझौते पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान के और सब लोग दौलताना साहब की तरह के नहीं हैं और वे लोग इस विषय पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो मौलिक बात इस समझौते में है वह यह है

"if the East Punjab Government to discharge the obligation to developed areas where water is scarce and which were underdeveloped in relation to parts of West Punjab."

इस समझौते में जो सब से बड़ी बात है वह यह है कि इसमें यह मान लिया गया है कि ईस्टर्न पंजाब विकसित नहीं है। वेस्टर्न पंजाब विकसित है। इसलिये हिन्दुस्तान को और ईस्टर्न पंजाब को पाकिस्तान की अपेक्षा ज्यादा पानी की आवश्यकता है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

फिर इसके बाद इस समझौते की एक मौलिक बात और है .

"give reasonable time to enable the West Punjab Government to tap alternative sources"

यह दूसरी मौलिक बात है कि जब तक उन नहरो के लिये जो कि हिन्दुस्तान की तरफ से वैस्ट पाकिस्तान को जाती है पानी का दूसरा प्रबन्ध न हो तब तक हिन्दुस्तान उनको पानी दे । मै नम्रता के साथ कहना चाहता हू कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान की तीनो नदियो का पानी अपनी नहरो के लिए है वह उसी वक्त तक हिन्दुस्तान मे लेगा जब तक कि वह आल्टरनेटिव मीन्स उसके वास्ते खोज नही लेता है ।

इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने सन् ५४ मे यह प्रपोजल रखा । पाच बरस के अन्दर पाकिस्तान आल्टरनेटिव मीन्स अपने लिये खोज ले ताकि हिन्दुस्तान का जो पानी है वह हिन्दुस्तान को मिल सके वह इस पानी को अपने अडर डेवेलपड एरिया के लिये काम मे ला सके ।

मै आपको जरा और पीछे ले चलना चाहता हू । सन् १९४७ के समझौते के बाद सन् १९४९ मे हिन्दुस्तान ने एक निवदन किया कि एक ज्वाइंट कमीशन दोनो मुल्को का होना चाहिये और वह कमीशन कोई वायाबीडिया निकाले कि जिसके द्वारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनो देशो की समस्या हल हो सके ।

इसके पश्चात् ४ अगस्त, १९५१ को डेविड ई० लिलथेल ने कोलियर्स जनरल मे एक आर्टिकल लिखा "एनादर कोरिया इन मेकिंग" । उन्होने समझा कि यह पानी का विवाद नार्थ और साउथ कोरिया के विवाद की तरह का सवाल है । लिहाजा उन्होने एक सुझाव दिया । उसके आधार पर सितम्बर सन् १९५१ मे इंटरनेशनल बैंक के प्रेसीडेंट ब्लैक साहब से एक प्रोपोजल रखा । वह यह था कि बैंक दोनो देशो के इंजीनियरों को एकत्रित करेगा । मै यह बात साफ कर दू कि हमने इंटरनेशनल बैंक को अपना आरबिट्रेटर मुकर्रर नही किया था । बल्कि इंटरनेशनल बैंक ने अपनी सरविसेज इस वास्ते दी थी कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के जो इंजीनियर है वे एक जगह मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि दोनो देशों का काम चले । दिनाक ८ नवम्बर, सन् १९५१ को ब्लैक साहब ने हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को अपना यह प्रोपोजल भेजा । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह सजेस्ट किया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के इजीनियर्स की एक वर्किंग पार्टी इस नहरो पानी के विवाद का हल खोज ।

इसके बाद एक बात और साफ करना चाहता हू कि यहा पर १५ मई, सन् १९५७ को इरिगेशन के मिनिस्टर साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुये कहा था कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का यह स्टैंड था कि आपस मे समझौता करने मे बैंक की सहायता मिल सके । सिर्फ यही परपज इस इटरनेशनल बैंक का था, अर्थात वह समझौते का साधन मात्र बन सके इसके अलावा और कोई परपज नही था ।

मई जून सन् १९५२ मे वाशिंगटन मे दोनो पार्टिया मिली और उस वक्त इडिया ने एक प्लान रखा । आप जानते हैं कि पजाब मे ६ नदिया है, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास । इन ६ नदियो मे से तीन यानी व्यास, रावी और सतलज हिन्दुस्तान मे बहती है और फिर सतलज, रावी पाकिस्तान में जाती हैं । बाकी तीन नदियां पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान को सीचती हैं । शायद इंटरनेशनल बैंक यह भूल गया कि वहां पर एक नदी काबुल नाम की भी है । यह

नदी काफी पानी लाती है जो कि सिंध में मिलता है। इस प्रकार आप देखें कि पाकिस्तान में चार नदियों का पानी आता है, जब कि ईस्टर्न पंजाब में सिर्फ तीन नदियों का पानी आता है, जो कि बहुत कम है। इसका आगे चल कर मैं विश्लेषण करूंगा।

हिन्दुस्तान ने जो प्रोपोजल रखा उसमें यह था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों हिस्सों की नदियों में ११९ मिलियन एकड फीट पानी आता है। हिन्दुस्तान ने कहा कि हमको ईस्टर्न रिवर्स अर्थात् सतलज, व्यास और रावी का सारा पानी मिले और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका ७ परसेंट पानी सिर्फ हमको और मिले। अर्थात् ११९ मिलियन एकड फीट पानी में हिन्दुस्तान ने अपने लिये २९ मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रोपोजल रखा। हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान से कहा जितना पानी वैस्टर्न रिवर्स में है उसका ९३ परसेंट आप ले लीजिये और हमें सिर्फ ७ परसेंट पानी दे दीजिये। चूंकि हिन्दुस्तान ने एक प्रोपोजल रखा तो पाकिस्तान को भी एक प्रोपोजल रखना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जो तीन नदिया बहती हैं उन में से ३० परसेंट पानी पाकिस्तान को और चाहिये। आप देखें कि पहले एग्रीमेंट से मालूम होता है कि ईस्टर्न पजाब अंडरडेवेलप्ड है। पर पाकिस्तान कहता है कि हिन्दुस्तान अपने पानी में से पाकिस्तान को और पानी दे और जो वैस्टर्न रिवर्स है उनके पानी में से हम एक छटाक पानी भी हिन्दुस्तान को नहीं देंगे। आप देखें कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के प्रोपोजल्स में कितना अन्तर है। इस प्रकार पाकिस्तान का यह प्रोपोजल था कि १०२ मिलियन एकड फीट पानी पाकिस्तान में रहेगा और आपको सिर्फ १५ मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना पानी ईस्टर्न और वैस्टर्न पंजाब में है उसका सिर्फ ९ परसेंट भारत को मिलेगा बाकी सब इडस बेसिन का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिये।

इसके बाद बैंक ने दूसरा प्रोपोजल रखा। बैंक ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं। बैंक ने कहा कि अच्छा भाई हिन्दुस्तान तुम २२ पर सेट ले लो। बैंक ने कहा कि कुल ११९ मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें से ९७ मिलियन एकड फीट पानी पाकिस्तान को दे दिया जाये और २२ मिलियन एकड़ फीट हिन्दुस्तान को दिया जाये, अर्थात् जो २९ मिलियन एकड फीट के लिये हिन्दुस्तान का प्रोपोजल था उसको बैंक ने ७ मिलियन एकड फीट पानी कम कर दिया। पाकिस्तान ने १०२ मिलियन एकड फीट पानी की माग की थी उसमें से उन्होंने पाकिस्तान को ९७ दे दिया। इस प्रकार घाटे में हम रहे। इस प्रोपोजल के अनुसार बैंक ने पाकिस्तान के हिस्से में कुल पाच पर सेंट कम किया और हिन्दुस्तान के हिस्से में सात पर सेंट कम कर दिया। जैसा कि मैंने अभी कहा है, इस सारी बातचीत में काबुल नदी को बिल्कुल भुला दिया गया है। उसमें बहुत पानी आता है। लेकिन उसका मेनशन तक नहीं किया गया है। बैंक ने दूसरी प्रोपोजल यह रखी कि संक्रमण काल में—ट्रांजीशनल पीरियड में—भारत पाकिस्तान को पानी देता रहेगा। वह तब तक देता रहेगा, जब तक कि लिंक कैनाल्ज तैयार न हो जाये। इस सम्बन्ध में पाच वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हू कि वह अवधि तो समाप्त हो चुकी है। तीसरी प्रोपोजल यह थी कि दोनों देशों में जो निर्माण होगा, उसका खर्च दोनों देश देंगे। यह भी तय किया गया कि भारत केवल उस खर्च के लिये जिम्मेदार होगा, जो कि रीप्लेसमेंट बेनिफिट आफ वाटर के कारण उसके हिस्से आयेगा। हम लोगों ने अखबारों में पढा है कि पाकिस्तान ने प्रोपोजल किया था कि सिन्ध नदी से पानी निकाल कर हिन्दुस्तान की कैनाल्ज में डाल दिया जाय और उसका खर्च हिन्दुस्तान दे। यह तो वैसी बात है कि कलकत्ते का पानी दिल्ली लाया जाये। यह तो बिल्कुल उल्टी बात

[श्री रघुनाथ सिंह]

है । मैं समझता हू कि हिन्दुस्तान ने इस बात का स्वीकार न करके अच्छा किया है । बैंक के जिन सुझावो का मैंने अभी जिक्र किया है, हिन्दुस्तान ने उनको मान लिया । लेकिन पाकिस्तान ने नही माना । जिसका परिणाम यह है कि नहरी पानी विवाद बराबर चल रहा है । वह कब तक इस तरह चलता रहेगा, यह पता नही है । इसका अन्त होना चाहिये ।

सन् १९५४ मे एक और स्कीम निकाली गई । को-आपरेटिव वर्क के बेसिस पर एक प्लान बने । दिनाक २१-६-५५ को वाशिगटन मे एक एड हाक समझोता हुआ, जिसमे यह तय हुआ कि १-४-५५ से ३०-६-५५ तक हिन्दुस्तान पाकिस्तान को पानी दे । दिनाक ३०-१०-५५ को वाशिगटन मे एक दूसरा एग्रीमेंट हुआ जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि हिन्दुस्तान १-१०-५५ से ३१-३-५६ तक पाकिस्तान को पानी दे । इसके बाद एक तीसरा एग्रीमेंट २८-९-५६ को वाशिगटन मे हुआ, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान को १-४-५६ से ३१-३-५७ तक पानी देगा । मैं यह पूछना चाहता हू कि आज, १९५८ मे, हम इस किस एग्रीमेंट के आधार पर पाकिस्तान को पानी दे रहे है । Where is the agreement? मैं दावे के साथ कहता हू कि अगर हम १९५८ मे भी पाकिस्तान को पानी दे रहे है तो वह नाजायज तौर पर दे रहे है ।

मैं आपके ध्यान मे यह बात लाना चाहता हू कि इन एग्रीमेन्ट्स के सम्बन्ध मे कानूनी इत्यादि करने मे भारत का क्या खर्च हुआ । शायद वह आपका ही सवाल था, जिसके उत्तर मे इस सदन मे बताया गया कि इस सम्बन्ध मे १०,८१,००० रुपया खर्च कर दिया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि हमारे देश को फारेन एक्सचेंज की दिक्कत का सामना करना पड रहा है, लेकिन फिर भी सात आठ पन्ने के छोटे से एग्रीमेंट के लिये इतनी बडी राशि वाशिगटन मे खर्च कर दी गई । मैं समझता हू कि इसके उत्तर में शायद कहा जायेगा कि आखिरकार सारी दुनिया एक है, हम पंचशील के सिद्धान्त को मानते है । को-एग्जिस्टेंस मे विश्वास रखते है । इसलिये हमको आपस मे सघर्ष नही करना चाहिये लडना नही चाहिये । मैं आपको कुछ आकडे बताना चाहता हू । सारे इन्दस बेसिन मे, अर्थात् जब ईस्ट और वैस्ट पजाब एक थे, तो उस सारे क्षेत्र में ६ ०,५,००,००० एकड भूमि खेती लायक थी, पाकिस्तान के हिस्से ३,९०,००,००० एकड भूमि और भारत के पास सिर्फ २ ६०,००,००० एकड भूमि आई । पार्टीशन के परिणामस्वरूप भारत को सिर्फ ५० लाख एकड सीची हुई भूमि मिली और पाकिस्तान को २ १०,०० ००० एकड सीची हुई भमि मिली । अर्थात् भारत को १९ सैकडा और पाकिस्तान का ५४ सैकडा सीची हुई भमि मिली । यह पार्टीशन की विभीषिका थी । हमारे सिख और जाट भाईयो ने अपने खून से वैस्ट पंजाब को सीचा था अपनी जान लडाई थी और इस तरह रेगिस्तान को हरी भरी भूमी बना दिया था । वे लोग विस्थापित किये गये । इसके उत्तर मे यह कहा जायेगा कि यह तो होता ही है । दुनिया मे हर एक आदमी को जीने का अधिकार है, लोग तो दान दिया करते है । इस सम्बन्ध मे मैं आपको आबादी के आकडे देना चाहता हू । ईस्ट पजाब की आबादी २,१०,०० ००० है जब कि वैस्ट पजाब की आबादी २,५०,००,००० है । आबादी में सिर्फ ४० लाख का फर्क है । और भूमि में १९ और ५४ परसेंट का फर्क है । यह क्या न्याय है ? हाथी साहब को पता होगा कि भारत में—यहा मेरा मतलब ईस्ट पजाब से है—२,१०,००,००० एकड भूमि के लिये सिचाई की व्यवस्था नही है, जब कि वैस्ट पंजाब में सिर्फ १,८०,००,००० एकड़ भूमि के लिये सिचाई

की व्यवस्था नही है । जहा तक पर कैपिटा भूमि का सवाल है, भारत में सींची हुई भूमि प्रति व्यक्ति के ऊपर सिर्फ २४ एकड है जब कि पाकिस्तान में ---वैस्ट पंजाब में--- वह ८० एकड है अर्थात् पाकिस्तान में वह तीन गुना ज्यादा है । आप पूछेंगे कि पानी कितना आता है और उसका बटवारा कैसे हो । इन्दस बेसिन में १६८ मिलियन एकड फीट पानी होता है, जिसमे से ८० पर सेंट तो वैस्ट पंजाब मे है और सिर्फ २० पर सेंट ईस्ट पजाब में है । अगर सतलज, व्यास और रावी का एक एक बूंद पानी भी यूटिलाइज किया जाय, तो भी २० परसेंट से ज्यादा पानी नही मिल सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने सब पानी का यूटिलाइज करे, तो वह ८० परसेंट पाता है । पाकिस्तान की नहरो मे ६,६० ०० ००० एकड फीट पानी होता है, जब कि हिन्दुस्तान मे सिर्फ ६०,०० ००० एकड फीट पानी से सिचाई होती है । इसमे अपनी अपनी अक्ल, अपनी अपनी बुद्धि का भी सम्बन्ध है । हम लोगो ने भाखरा डैम बनाया और पानी का ठीक इस्तेमाल करने के उपाय किये है । मै आपको इंटर-नेशनल बैंक की आबजर्वेशन बताना चाहता हू । उसने कहा है कि अरब सागर मे पाकिस्तान का ३५० ०० ०१० एकड फीट पानी खराब होता है । हिन्दुस्तान अपने लिये सिर्फ १६ परसेंट पानी प्रयोग करता है । अगर पाकिस्तान चाहे तो वह ८० परसेंट से अधिक पानी का प्रयोग कर सकता है और अपनी एक एक इंच भूमि को सींच सकता है लेकिन हम ईस्ट पजाब की पूरी भूमि नही सींच सकते है । एग्रीमेंट की शर्तों से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को डेवेलप्ड लैंड मिली है और हमको अन-डेवलप्ड लैंड मिली है । इसलिये दुनिया की सिम्पथी दुनिया की सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिये । भूखे हम है । वे भूखे नही है । उनके पास साधन मौजूद हैं । खेत मौजूद हैं । पर-कैपिटा ८० एकड उनका है । पर-कैपिटा २४ एकड हमारा है । वे खुशहाल हैं । इस लिहाज से हम नही है । मैं दुनिया से कहना चाहता हू । वह इन फैक्टस को आखे खोल कर देखे और समझे कि हिन्दुस्तान के साथ क्या अन्याय हो रहा है ।

पाकिस्तान ने बैंक की बात भी नही माना तो जून १९५७ मे वाइस-प्रेसीडेंट आफ वर्ल्ड बैंक हिन्दुस्तान आये । वह अप्रैल और मई में पाकिस्तान भी गये और उन्होंने प्लान को स्टडी किया । जुलाई १९५८ में जब पाटिल साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यह कहा कि कनक्रीट प्रोपोजल क्या है वह सामने नही आया है ।
He has only given advice
जुलाई १९५८ मे सवाल पूछा गया कि लदन मे जो कान्फ्रेंस हुई थी उसका क्या नतीजा निकला तो कहा गया कि पाकिस्तान का प्लान मिला है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं । दिनाक २१ जुलाई, १९५८ को फिर सवाल पूछा गया लेकिन फिर भी यही जवाब दिया गया कि पाकिस्तानी प्लान का स्टडी किया जा रहा है । दिनाक १२-८-५८ को हाफिज जी ने कहा और बडी मर्दानगी के साथ कहा कि Formula is one. एक फार्मूला है और वह फार्मूला यह है कि वैस्टर्न रिवर्स आर टु सप्लाई वाटर टु पाकिस्तान । इसमे हाफिज जी ने एक बात तो साफ कही । अभी इसी महीने मे पिछले महीने मे १६-१७ दिन हुए इस सदन मे यह उत्तर दिया गया था

India will not wait indefinitely for a settlement ignoring the needs of her own people

इससे पता चलता है कि स्थिति कुछ साफ हुई है । उस स्थिति को हमारे सामने रखा गया है । मैं चाहता हू कि हाफिज जी इस पर स्टिक करे । कहे कि जो वैस्टर्न रिवर्स का का पानी है उसको पाकिस्तान ले । और जो ईस्टर्न रिवर्स का पानी है उसे हम ले । हम अपनी गवर्नमेंट से तथा हाफिज जी से यह आशा करते है कि वे हमारी जो इस वक्त तक ढिलमिल नीति रही है, उसको त्याग देंगे और इस पोजीशन पर स्टिक करेंगे । मैं चाहता हू कि साफ तौर से यह कहा जाये कि

[श्री रघुनाथ सिंह]

न एक बूद पानी हम तुमको देंगे और न एक बूद पानी हम तुम्हारा लेंगे ।

हाथी साहब से जब एक सवाल पूछा गया कि आखिर बाबा यह बात कब तक चलती रहेगी तो उन्होंने कहा कि सन् १९६२ तक । अभी पाकिस्तान को पानी देने की चार बरस की लीज आपने और दे दी है और आपने कहा है कि १९६२ के बाद हम पाकिस्तान को जो पानी देते है, वह बन्द कर देंगे । इस के बाद हमने पाटिल साहब से पूछा कि आखिरकार साहब आप कब तक वेट करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि We will not wait indefinitely for a settlement ignoring the needs of our own people. मै कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की यह नीति है तो उसको इस नीति पर स्टिक करना चाहिये और इस वास्ते स्टिक करना चाहिये कि २ करोड़ ६० लाख भूमि जो ईस्टर्न पंजाब मे है जिसमे से कि १ करोड १० लाख भूमि ऐसी है जोकि बंजर पडी हुई है, जो सीची नही जा रही है, उसको सीचने के लिये ईस्टर्न रिवर्स का एक एक बूद पानी मिल सके, उसका उपयोग भारत मे किया जा सके ।

हाथी साहब से जब यहां एक बार सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि दो तरह के खाते है, एक डिसप्यूटिड खाता है और दूसरा अनडिसप्यूटिड खाता है । हमारे यहा खाता बहुत जल्दी खुल जाता है । बजाय इसके कि मामले को तय किया जाये, हम खाता खोल देते है, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया । नतीजा यह हुआ कि इस खाते मे जो हमारा २७ लाख ८१ हजार ८३१ रुपया पाकिस्तान के जिम्मे बाकी है उसको पाकिस्तान ने सन् १९५० मे हमे अदा नही किया है, उसमें से एक पैसा भी नही दिया है । इसके साथ ही साथ जो डिसप्यूटिड एमाउट है वह करीब ९७ लाख ८७ हजार ९८० रुपया है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक अदा नही किया है । आप अच्छे महाजन हैं जब तक भी कोई खाना चाहे उसको खिलाते जाना चाहते हैं । चाहे वह आपको आपका रुपया दे या न दे । आप यह कहते जाते हैं कि हम खिलावगे जरूर । इस नीति का मै समझता हूं कि कहीं न कही अन्त होना चाहिये । इसके साथ ही साथ १९४७-४८ मे इलैक्ट्रिक ड्यू के तौर पर १ लाख ८४ हजार ७०९ रुपया भी बाकी है ।

दिनाक ५-९-१९५७ को एक मोक्षन कालिंग एटेंशन का दिया गया था । उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सफा १२४२ पर दिया था । उनसे पूछा गया । पाटिल साहब के जवाब को तो आप छोड़ दे आप बताये कि पाकिस्तान के जिम्मे कितना रुपया है । कुछ मालूम तो हो कि वह कैसा व्यापारी है जोकि उधार मे कर देता भी नही है और उसका पेट भरते जाते है । क्या आप के यहा भी कोई खाता है ? उन्होंने कहा कि यहा भी खाता खुला हुआ है और उसमे तीन तरह की कैटेगरीस हैं । उसमे उन्होंने बताया कि एक पार्टिशन ड्यूम है जो करीब ३०० करोड़ के हैं । इसमें एक कैटेगरी ५० करोड की है । यह कुछ अधिक या कुछ कम हो सकती है, यह पार्टिशन ड्यू मे है । इस पर एक माननीय सदस्य ने झट से सवाल पूछा कि वह सेपेरेशन करेंसी का क्या मामला है ? इस पर कहा गया कि ४९ करोड रुपया उसमें से भी-पाकिस्तान के जिम्मे है । इसके बाद जो डिफेंस स्टोर सप्लाई किये गये उनके बारे में प्रश्न किया गया है । इस पर कहा गया कि १३ करोड उसमें भी बाकी है । इस तरह से कोई ११२ करोड़ रुपया भारत का पाकिस्तान के सिर पर मौजूद है । इतना होने पर भी हम उनको रुपया देते हैं, उनको पानी देते चले जा रहे है । एक तरफ तो वहां जिहाद का नारा लगाया जा रहा है दूसरी तरफ हम उनको खिलाते पिलाते जा रहे हैं । आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान

के बजट का ८० प्रतिशत फौज के ऊपर खर्च हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना रुपया फौज पर क्यों खर्च किया जा रहा है? इस फौज को किस के खिलाफ इस्तेमाल करना वे लोग चाहते है? यह फौज हमारे खिलाफ तैयार हो रही है। इस फौज को हम पानी देते जा रहे है। इस फौज को हम खिला रहे हैं। और क्या हम इसको इस लिये खिला रहे है कि यह हम पर हमला करे और आकर हमारे साथ लड़े? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने घर में आबाद रहे और हम अपने घर में आबाद रहें। हमें उनको साफ साफ कह देना चाहिये कि बाबा तुम्हारा पानी तुम्हारे पास और हमारा पानी हमारे पास, तुम्हारी नदिया तुम्हारे पास और हमारी नदियां हमारे पास।

एक बात मैं और कहना चाहता हू। एक पार्टिशन कमेटी बनी थी। उसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ बटवारे किये। आखिरकार हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान भी सावरेन है, हम भी सावरेन है। हमारे देश मे जो नदियां है तथा उनका जो पानी है, वे हमारी है और पानी हमारा है और पाकिस्तान मे जो नदियां तथा पानी है वह उसका है। अगर आज पाकिस्तान यह कहता है कि जो हिन्दुस्तान की नदियो का पानी है, उसमे उसका भी हिस्सा है, तो इसका मतलब यह है कि वह हमारी सावरेनटी में हिस्सा बटाता है। इसका यह मतलब होगा कि हिन्दुस्तान की भूमि पर आप पाकिस्तान का कब्जा मानते है। इस हमारी भूमि में से एक इच भूमि पर भी उसका कब्जा नही माना जाना चाहिये। ऐसा करके आप पाकिस्तान को एक साझीदार बनायेंगे। वह नहीं होना चाहिये। मै चाहता हूं कि इस पालिसी का अन्त हो।

आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाले चिल्लाते हैं कि राजस्थान को सींचने के लिये कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था करने की स्कीम आज नही बनी है। यह स्कीम तो बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने मे बनाई गई थी। सन् १९०२ में श्री जे० विलसन ने राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था करने की स्कीम बनाई थी और कहा था कि राजस्थान को पंजाब की नदियों में जो एक्सट्रा पानी है, पहुचाया जाना चाहिये। जब यह बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को क्यो बीच मे घसीटा जाता है। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक थे, जब इस मुल्क का बटवारा नहीं हुआ था, जब सब मिल जुल कर रहते थे, उस वक्त एक स्कीम बनी थी कि राजस्थान को पंजाब की नदियो से पानी पहुंचाया जाये। अब अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ...

Shri Harish Chandra Mathur: The canal is already there

श्री रघुनाथ सिंह: मैं सन् १९०२ की बात कह रहा हूं, आज से कोई ५५ साल पहले की बात। हमने कोई नई बात नही की है। हमने कोई नई स्कीम नही निकाली है। हमने कोई नई पालिसी तय नही की है। आज से करीब ५५ बरस पहले जो पालिसी थी, जो स्कीम थी, उसको हमने पुरानी रद्दी फाइलों से निकाल कर अमली रूप देने की कोशिश की है। यह स्कीम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब दोनो देशो के लोग एक थे, ने मिल कर तय की थी। अबहम उसको कैरी-आउट कर रहे है।

पाकिस्तान ने एक और नया नारा उठाया था। उसने कहा था कि जो इटरनैशनल कोर्ट हेग मे है, उसको यह सारा मामला सुपुर्द किया जाये। आप जानते ही है जो सावरेन बाडीस होती हैं जब तक वे रजामन्द न हों, मामला वहां नही जा सकता है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

हिन्दुस्तान ने इस कोर्ट को मामला न सौंपने की बात कह कर बुद्धिमानी की बात की है। मैं आपको दो और मिसालें बतलाना चाहता हूं। अमरीका और मैक्सिको के बीच भी कैनाल वाटर डिसप्यूट चल रहा है। अमरीका और कनाडा में भी कैनाल वाटर डिसप्यूट चल रहा है। ये डिसप्यूट ८० वर्ष पुराने हैं। हालांकि इतने पुराने ये डिसप्यूट हैं फिर भी मामला आर्बिट्रेशन के लिए नहीं सौंपा गया है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये स्टेटस सावरेन हैं। अपनी अदालतों में ही वे मुकदमा ले जायें। अगर हिन्दुस्तान सावरेन है और पाकिस्तान सावरेन है तो हमको आर्बिट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अमरीका, कनाडा मैक्सीको में ८० वरस से इसी तरह का मामला चल रहा है। हमें भी उसी को कायम करना चाहिए। हमको किसी आर्बिट्रेशन के झमेले में नही पड़ना चाहिए। हमारी जो पालिसी है वह बिल्कुल साफ होनी चाहिये। हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि हमें अपनी एक करोड़ १० लाख भूमि को सींचना है जिस में इस समय सिचाई की कोई व्यवस्था नही है। हमारा जो पानी है, वह इस काम में आना चाहिये और यह जो घिस घिस ढिम ढिम और मिस मिस की पालिसी है, इसका अन्त होना चाहिये। इस अवस्था का अन्त होना चाहिये। हाफिज जी जब यू० पी० में थे तो अपनी स्पष्टवादिता के लिये बहुत मशहूर थे और मैं समझता हू कि जिस तरह से उन्होंने इस बारे में साफ साफ स्टेटमेंट्स दिये, कुछ ठोस कदम उठायेंगे।

मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की जनता हिन्दुस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है। और हिन्दुस्तान की जनता भी पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है। हम दोनों भाई भाई की तरह से हैं। भाई की तरह से, पड़ौसी की तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग युद्ध के नारे लगाते है और 'फाइट, फाइट, फाइट' कहना चाहते हैं उन से मैं कहूंगा कि अगर तुम 'फाइट, फाइट, फाइट' कहोगे तो पहले तो हम 'शांति, शांति, शांति' कहेंगे, पर अगर तुम महमूद गजनवी की तरह से, गोरी की तरह से, नादिरशाह और तैमूर लंग की तरह से हिन्दुस्तान की दौलत को लूटने के लिये आओगे तो ठीक नहीं होगा। आज पुराना जमाना बीत गया, आज हिन्दुस्तान आजाद है। तुम कहते हो कि हमारे बच्चे और स्त्रियां लड़ेंगे, मैं कहूंगा कि हमारे बच्चे और स्त्रियां अपने को कुर्बान कर देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, इस वास्ते कि दोनों मुल्कों में शांति हो।

Shri Goray (Poona): After my hon. friend Shri Raghunath Singh has spoken, I would not like to repeat the facts that he has placed before the House, nor would I like to...

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may resume his seat for a minute. I have got about thirteen names of hon. Members who desire to speak.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): And one more

Mr. Deputy-Speaker: So, there are fourteen in all

श्री रघुनाथ सिंह : इस के वास्ते और टाइम मिलना चाहिये, यह बहुत अहम मसला है।

उपाध्यक्ष महोदय . आप ने शायद मांगा ही इतना था। मेरा तो इस में कोई दोष नही है। अगर इतने मेम्बर्स को ऐकामोडेट करना है और उन को टाइम देना है तो जरूरी है कि वक्त की पाबन्दी की जाये, और अगर मेम्बर साहबान इस से ऐग्री करते हो तो दस दस मिनट हर एक मेम्बर के लिये रक्खा जाये।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोजपुर) : जिन आदमियों ने इस बहस को इनिशिएट किया है और कम से कम उन मेम्बर्स को जिन पर इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट का असर पड़ता है और जो.....

उपाध्यक्ष महोदय : उन को मैं १५, १५ मिनट दूंगा।

Shri Goray: I was saying that after the speech of my hon. friend Shri Raghunath Singh, it was not necessary for me to place before this House once again the detailed picture which he has given us.

This Indo-Pakistan canal water dispute is, in my opinion, an illustration of the vacillating policy, the weak policy, that our Government has been pursuing not only in this respect but in all matters of Indo-Pakistan relations that have cropped up after Independence. The picture that we had before us when the Partition took place was roughly like this: that the Indus river basin was divided, and as we witnessed throughout this country, the division did not take place on any scientific basis. The basin was divided arbitrarily, and naturally, this division resulted in hardship

Reference was just now made to the observations of Mr. Lilienthal. He had said that:

> "No one seems to know why the flow of the valley's life-blood was so carelessly handled in the time of Partition."

In this single sentence, he had very succinctly and very pointedly summed up the whole situation.

The Indus river basin was, and is, and will be bringing down from the Himalayas 168 million acre-feet of water; out of this, the only volume of water that was used by Pakistan was 66 million acre-feet; India was using 9 million acre-feet; and the rest of the water, that is, about 75 million acre-feet was just allowed to flow into the sea. That means that it was wasted. If any scientific attitude had been taken, and this Indus basin water was not utilised or exploited as a bone of contention between the two countries, if we had approached this problem in a scientific manner, treating the whole of the Indus basin as one unit, then it would have been possible to solve this dispute amicably and come to a settlement that would have brought blessings to all of us, not only to the residents of India but to the residents of Pakistan also.

Now, it has happened that though Pakistan had so much opportunity of using this water, they just allowed it to go to the sea. They thought that it would be better to take advantage of the weak position that India has been taking all along. I do not like to blame Pakistan here. If we take an attitude which is always weak-kneed, and if though we know that justice is on our side, we take a position in which we appear to the world as if there is something of a guilty conscience in our own mind, then, I do not know why our opponents should not take full advantage of our psychology. That is exactly where Pakistan has scored over us.

I do not want to trace the whole history. But the World Bank is there.

Shri Raghunath Singh: It is not an award. It is only a proposal.

Shri Goray: Yes, it is only a proposal. Concerning their proposal, in this publication brought out by the Government of India, they say in a very self-righteous manner that:

> "The new canals in India, under the divisions of waters envisaged in the Bank proposal, would be much more expensive than if all the waters available to India and indispensable for a normal development would have been utilised therein. Nevertheless, India has decided to accept the

[Shri Goray]

> principles of the Bank proposal in the interests of a speedy and constructive settlement.".

And by way of peroration, they add.

> "As in the past, India has shown her goodwill by offering to make far-reaching sacrifices.".

I do not know who had asked India to make these sacrifices. I entirely agree with my hon. friend when he says that when we are dealing with Pakistan, let us remember that Pakistan is a sovereign nation and so is India. When between two sovereign nations, some distute arises, one nation is not expected to make far-reaching sacrifices to placate the goodwill of the other. You have to stand on your own; you have to say that this is what belongs to you, and as you are not demanding something from your opponent, you are going to keep it

It has been said that the merit of the Bank proposal was that it was a very simple proposal. It divided the river Indus, with the Kabul river on that side, and also the Jhelum and Chenab on that side for Pakistan.

Shri Raghunath Singh: They have not mentioned the Kabul river.

Shri Goray: It was so obvious that probably thay did not think it necessary to mention it. On this side, we had the Beas, the Ravi and the Sutlej. Therefore, this proposal was accepted by India, and they said that if this proposal was accepted by Pakistan as well, it would lead to a very simple solution, we would manage or manipulate and train our rivers, and they would manage their rivers and even if there was a little sacrifice on our part, we would not mind.

Now once our Government had taken up this position, they ought to have stood by it. They ought to have told them that no more negotiations are necessary. But the negotiations have gone on. Now—as you have given me only a limited time—I would only say that the disadvantages are all on our side. What have we gained? We have gained nothing. As this pamphlet says, we have made far-reaching sacrifices. But that is not all. I would like to point out on how many counts India is the loser. India has been the loser firstly with regard to the financial arrangements. The financial arrangements between Pakistan and India show that Pakistan has ceased to give India anything after 1950. For the last 8 years all charges under the head 'Disputed charges' have been withheld and now the sum has swelled to nearly Rs. 1 crore.

The other point we have been the losers on is, that we have got only 20 per cent of water from the Indus basin rivers and about 80 per cent of the water has been allowed to go to Pakistan Though we ought to have got more, we said, 'All right; we are satisfied with this'. There also we have lost. As my hon. friend has just now pointed out, Engineer Wilson when he gave his opinion before the Irrigation Commission of Rajasthan in 1902 said that "untold millions of acres of land in Rajasthan could be irrigated from the Punjab rivers." But now that has become a dream, because it can no longer be possible; with these three rivers, which have only 20 per cent of the water of the Indus Basin, it is not possible for us to irrigate all the land that we have. Therefore, we are losers on that count also.

The third thing is—it is, again, a very strange thing—that even according to the World Bank proposals, India would have been perfectly in the right if she had said that after 1959 'We shall not give you a drop of water'. There also we have become magnanimous. We have said that though we are accepting the World Bank proposals so far as the

water allotment is concerned,—only 20 per cent.; we are satisfied with it—we are not accepting the other proposals of the World Bank; on the contrary, we are saying that though they have said that in 1959 we could stop all the water that we are now giving to Pakistan, we will continue to give them till 1962.

I would like the Minister to tell us why is it that he is taking such positions. Why is it that he is not sticking to anything? The Government acccpted the World Bank proposals. All right. Then stick to them. But they do not stick to them They add something to them which, again, is to our disadvantage.

Therefore, I am saying that once for all the Government of India should define their attitude towards this canal water dispute, and having defined that attitude, stick to it. What are they afraid of? They know that the whole country is behind them This is one of those problems where all the people are supporting them Not only that; people are saying that Government are unnecessarily committing themselves to a position which is not going to be of any advantage to us. This Government have developed a habit of committing themselves to a particular position without taking people into confidence. When we fought the elections, did the Party in power go to the people and say, 'This is the position we are going to take on the canal water dispute'? They did not do so, because if they had said so in Punjab, they would have known that they were not likely to get votes. Therefore, let Government not commit themselves; let them not go beyond the mandate that has been given to them; let them not go beyond the proposals suggested by the World Bank.

Therefore, I would request the Minister of Irrigation and Power to take up a stand. It is not a stand hostile to Pakistan It is a stand based on the World Bank proposals Let him stick to it and let him be sure that in doing that the whole country is behind him.

सरदार इकबाल सिंह : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस कैनाल वाटर डिस्प्यूट का जिक्र चल रहा है वह उस वक्त से चल रहा है जिस वक्त से कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान आजाद हुए और जिस के पहले पंजाब की नहरों, पंजाब के इरिगेशन का सिलसिला एक ढंग से चल रहा था। तकसीम के साथ-साथ जहां पर और बहुत सी मुसीबतें आईं, इरिगेशन का सिलसिला भी तकसीम हो गया। १६ नहरों में से पाकिस्तान पंजाब को १३ नहरें गईं और हिन्दुस्तान पंजाब को ३ नहरें मिलीं। जो नहरें उस वक्त रियासतों को जाती थी उन में से ११ नहरें वह थी जो कि बहावलपुर या मुल्तान के इलाके को सैराब करती थीं और सिर्फ एक गंग कैनाल थी जो कि बीकानेर के इलाके को सैराब करती थी। लेकिन हिन्दुस्तान ने पहले सन् १९४७ में और उस के बाद सन् १९४८ में एक समझौता किया था। आज सब से बड़ी कोशिश यह की जा रही है कि उस समझौते को बैकग्राउंड में डाला जाये और उस के बाद की जो बातें हुई उन को आगे रखा जाये।

इस समझौते में हिन्दुस्तान की तरफ से हमारे प्रधान मंत्री, उस वक्त के पंजाब के इरिगेशन के मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और श्री एन० वी० गाडगिल थे। पाकिस्तान की तरफ से गुलाम मुहम्मद और शौकत हयात, जो उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, और मियां मुमताज दौलताना थे। वही मियां मुमताज दौलताना आज दस साल के बाद पाकिस्तान की असेम्बली में और बाकी जगहों में कहते हैं कि सन् १९४८ का समझौता अन्डर डयूरेस किया गया था। आप यह जानते हैं कि उस वक्त अन्डर डयूरेस हिन्दुस्तान था न कि पाकिस्तान। उस वक्त

[सरदार इकबाल सिंह]

पाकिस्तान फीरोजपुर के ६ मील उत्तर मे आरजी नहरे बना रहा था । अब गग कैनाल के इलाके से, जहा से कि हम पानी लेते है, उस के पानी को काट कर दिपालपुर कैनाल मे डाले, इस को सामने रखते हुए सब से पहले हिन्दुस्तान की सरकार ने हरीका बैराज बनाने का फैसला किया ताकि कम से कम बीकानेर के इलाके के जो लोग है, पाच छ लाख आदमी, उन मे से किसी को पाकिस्तान नुक्सान न पहुचा सके । उस वक्त अन्डर ड्यूरेस तो हिन्दुस्तान के वह आदमी थे जिन के पानी को किसी वक्त काटा जा सकता था, और वही आदमी जो तब इस बात को करने मे कामयाब नही हुए, उन्होने खुद कहा था कि हिन्दुस्तान का हक है कि इन तीन नदियो का पानी ले । उस के बाद जब ऐसे हालात हुए कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की वह बात नही चली तो वर्ल्ड बैंक ने सजैस्ट किया कि एक इजीनियरिंग टीम बनाई जाये । उस के बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ तजवीजे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सामन रक्खी । हिन्दुस्तान की सरकार ने उन तजवीजो का मजूर किया लेकिन पाकिस्तान सरकार ने न सिर्फ उन को मजूर ही नही किया बल्कि वह दो तीन साल तक कहती रही कि हम उन की स्टेडी करते है । इस तरह मे उन्होने इतना वक्त गुजार दिया । उन तजवीजो मे हिन्दुस्तान का यह हक माना गया था कि जो तीन दरिया सतलज रावी और व्यास है उन का पानी उस को मिले ।

आप यह जानत है कि इन तीना दरियाओ का जो पानी है वह कुल मिलाकर २६ लाख क्यूसेक्स के करीब बनता है और पाकिस्तान को जो जो दरिया जाते है, जिन मे इन्डस और काबुल के साथ साथ चेनाब और झेलम भी है, उन का जो पानी है वह १४० लाख क्यूसेक्स के करीब बनता है जिस का प्रपोर्शन २० और ८० के करीब बनता है । उस मे से भी जो हिन्दुस्तान इस्तेमाल करता है वह सिर्फ ७ लाख क्यूसेक्स के करीब है । इस के बाद जब फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की तजवीज को नही माना, तो अगले साल वर्ल्ड बैंक ने एक नया प्रपोजल दिया । उस के बाद आलिफ साहब आये, उन्होने एक नई तजवीज रक्खी । आज हम इस हाउस में और इस के बाहर इस बहस को इस लिये उठाते है कि हिन्दुस्तान के लोगो क दिल मे, पजाब और राजस्थान के मुसलमानो के दिल में, शकूक पैदा होते है, जिस ढग से कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस पोजिशन को रक्खे हुए है कि आज हिन्दुस्तान के साथ जो कैनाल वाटर डिस्प्यूट है वह एक एकानामिक झगडा है ।

15.49 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान क लागो क अन्दर कुछ आम और उम्मीद थी कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम होगी ता उस के साथ उन के हालात भी बेहतर होंगे । आप जानते है कि जो पाकिस्तान की नहरे थी, जिन को पजाब की सरकार ने बनाया था, उन को जो पानी दिया गया वह साढे तीन क्यूसेक्स फी हजार क हिसाब से दिया गया और इस तरह की जो नहरे है उन को सिर्फ ढाई क्यूसेक्स फी हजार क हिसाब से दिया गया । इधर का इलाका भी बहुत खराब था ।

इसके साथ साथ यह हुआ जो कि सब से बडी बात है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई मजबूत स्टैड नही लिया। हमारा एक यही गिला है । आखिर जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप पाच साल क बाद, सन् १९५९ के बाद बेशक पाकिस्तान को पानी न दे तो क्यो हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि हम सन् १९६२ तक पानी देगे । दो तीन साल ट्राजिशनल ऐग्रीमन्ट्स किये,

उन का कम से कम एक फायदा जरूर होता था कि पाकिस्तान भी अपना डाटा हिन्दुस्तान को सप्लाई करता था और हिन्दुस्तान भी अपना डाटा पाकिस्तान को सप्लाई करता था। पिछले साल पाकिस्तान ने कोई ट्रांजिशनल एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि एक गलत बिना पर वर्ल्ड बैंक के पास गया और कहा कि देखो, हिन्दुस्तान ने हम को पानी नहीं दिया। हालांकि इस जून और जुलाई में सब से कम पानी पिछले २५ या ३० सालों में रावी, व्यास और सतलज में पहुंचा और पंजाब में कम से कम इस खरीफ की फसल कम बोई गई। इस का फायदा न उठाते हुए ह्यूमैनिटी के नाते पर हिन्दुस्तान ने कहा कि बेशक पाकिस्तान की नहरों को पानी मिलना चाहिये जब तक कि वह दूसरा कोई आल्टर्नेटिव अरेंजमेंट नहीं कर लेता। इस के बजाय कि पाकिस्तान इस ह्यूमैनिटेरियन मोटिव को समझे, उस ने एक नई शिकायत वर्ल्ड बैंक के पास भेज दी और इसके बाद वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर और हिन्दुस्तान के इंजीनियर उन से मिले। पता नहीं उन से मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक को खुफिया रिपोर्ट देगा या क्या करेगा। इस के बावजूद पाकिस्तान वाले एक लड़ाई का, कोल्डवार का सिलसिला चलाना चाहते हैं। इस के बाद आप जानते ही हैं कि सन् १९४८ के समझौते में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने यह माना है कि जिस वक्त दोनों सरकारें लिंक चैनेल्स बना लेंगी उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता विथड्राल खत्म हो जायेगा। उस के बाद पाकिस्तान कावन वाला वेदियन लिंक की चैनल्स बना कर अपर बारी दोआब के इलाके में पानी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। इसके बाद बल्लोकी सुलेमान की चैनेल बहावलपुर का जो इलाका था उसमें अपने ढंग से पानी सप्लाई कर सकते हैं। जब लिंक चैनेल्स बन जायेंगे और उसके बाद जब हम यह कहें कि सन् १९६२ तक भी पानी देंगे और इसलिये सन् १९४८ के भारत-पाकिस्तान नहरी पानी समझौते की जो शर्तें थीं उनको वे अपने ढंग से पूरा कर चुके।

इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर पंत जी ने इसी जुलाई में सरहिन्द कैनाल फ़ीडर का इफ़तिताह किया और उसके साथ साथ हम राजस्थान कैनाल वीक मना रहे हैं। अब अगर आप सन् १९६२ तक पानी देना चाहते हैं तो कम से कम हमें यह चीज तो जरूर माननी चाहिए कि इन नहरों में जिस ढंग से पानी की जरूरत ज्यादा होगी उस ढंग से हम उनको पानी की सप्लाई कम करते जायेंगे। मगर उसके बजाय आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी कहा है कि हमने एक नया कमिश्नर लगा दिया है जो यह देखेगा कि कम से कम उसी ढंग से पानी दे। जब आपकी नहरें ज्यादा बन रही हैं, जब आपकी नई नहरें चल चुकी हैं और नई नहरों को पानी की जरूरत है और यह वह इलाका है जिस इलाके में सब से ज्यादा लौंग स्टेपुल कौटेन पैदा होता है। आज हमारे देश को करोड़ों रुपये इसलिये बाहर देने पड़ते हैं कि लोग स्टेपुल कौटेन हमारे पास नहीं है और जिस इलाके के लोग इस उम्मीद पर बैठे थे कि जिस वक्त यह नहरें बन जायेंगी उस वक्त पाकिस्तान को यह पानी देना बंद कर दिया जायगा। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो १६ नहरें थीं, जितना इलाका है जितना भी पानी देना चाहिये वह देने के बाद हिन्दुस्तान का जो पानी आता है वह क़रीब ८० फ़ीसदी होता है, ८० और २० का रेशियो है।

अब जहां तक नये प्रपोज़ल्स का ताल्लुक़ है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में, इस मुल्क के लोगों में और खास तौर पर पंजाब और राजस्थान के बसने वालों में एक शुबहा पैदा होता है। सन् १९५४ के प्रपोज़ल्स में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि तीन दरिया उनके होंगे और तीन दरिया इनके

[सरदार इकबाल सिंह]

होंगे और उसके बाद तक़रीबन ५० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान पाकिस्तान को देगा। उसके बाद बहुत सी बातें सुनते रहे। इस बारे में हिन्दुस्तान के अखबार नहीं बल्कि बाहर के देश का एक अखबार यह लिखता है कि पाकिस्तान ने नये प्रपोजल्स के मुताबिक़ हिन्दुस्तान से ७०० करोड़ रुपया मांगा है। अब आप समझ सकते हैं कि ७०० करोड़ रुपये की रक़म कोई एक छोटी और मामूली रक़म नहीं है जिसको कि यों ही नजरअंदाज किया जा सके। इस तरफ़ के बसने वाले किसान और लोग भी तो यह समझते हैं कि हमें पानी ज्यादा मिकदार में और ज्यादा दिनों के लिए मिल सकेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान के जो बाहर भाई रहते हैं वे हमारे पानी के मसले और हमारी जरूरियात को नहीं समझ सकते। गर्मियों और सर्दियों के दिनों में पानी की जरूरत में बहुत फर्क है। सर्दी के दिनों में इन तीन दरियाओं में जो हिन्दुस्तान को आई है कुल तक़रीबन ८ हजार क्युसेक्स पानी होता है और इसलिए पंजाब की जो नहरें हैं मसलन् सरहिन्द कैनाल और दूसरी नहरें महीने में सिर्फ क़रीब १५ दिन चलती हैं, आल्टरनेटिव ढंग से चलती हैं और उनमें तक़रीबन आधा या एक-तिहाई के करीब पानी होता है। सर्दियों में पानी की बहुत जरूरत होती है और अगर आप सर्दियों में पाकिस्तान को पानी देना मंजूर करते हैं, जब कि आपके अपने रिजरवायर्स बने नहीं हैं और जब कि उनके लिंक चैनेल्स बन चुके हैं तो मैं समझता हूं कि आप उस हालत में हिन्दुस्तान के लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। अलबत्ता अगर उनके लिंक चैनेल्स न बने हुए होते तो मैं यह कह सकता हूं कि आपको उनको पानी देना चाहिये था। लेकिन जब उन्होंने लिंक चैनेल्स बना लिये हैं और जब सर्दियों के लिए उनको पानी मिल सकता है तो फिर सर्दियों में आप उनको इतनी वाटर सप्लाई दें जब कि हिन्दुस्तान के लोगों को १० दिन पूरा पानी मिलता है और दस दिन आधा पानी मिलता है और दस दिन बिलकुल उन नहरों में पानी नहीं होता, ठीक और मुनासिब नहीं जंचता।

अगर आप यह नये प्रपोजल्स मंजूर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको हिन्दुस्तान के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी और उनकी जरूरत का पानी उनको जरूर सप्लाई किया जायगा। यह चीज हिन्दुस्तान का अखबार नहीं बल्कि लन्दन का "एकोनामिस्ट" अखबार लिखता है कि उन्होंने ७०० करोड़ का प्रपोजल दिया है और यह ७०० करोड़ का प्रपोजल जो पाकिस्तान ने किया है वह सिर्फ इसलिए दिया है कि वह दो बातें चाहता है। एक तो यह कि सन् १९६२ के बाद भी पानी ले और दूसरे यह कि किसी ढंग से इस इश्यू को कोल्ड वार इश्यू बना कर दुनिया के दायरे में इसको ले जाकर हमारे खिलाफ प्रचार करे कि देखिये हिन्दुस्तान हमारे साथ कैसी नाइंसाफी बर्त रहा है, हमें पानी के लिए तरसा रहा है। इसलिए मैं अपने इलाके के लोगों की तरफ से सरकार की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस नहरी पानी की समस्या के बारे में एक नई और मजबूत पालिसी अख्तयार करे।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जिस इंजीनियर ने इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट के सिलसिले में हिन्दुस्तान की नुमायन्दगी की है वह एक बहुत काबिल इंजीनियर है। हमारे गुलाटी साहब पंजाब के बेहतरीन इंजीनियरों में से एक हैं लेकिन दरअसल बात यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार इस मसले को पार्ट टाइम मसले की तौर पर देखती है जबकि पाकिस्तान का सब से बेस्ट वेन इंजिनियरिंग का सेक्रेटरी होता है और पाकिस्तान का सब से अच्छा इंजीनियर बातचीत में हिस्सा लेता है। मैं इस से इंकार नहीं करता कि हमारे इंजीनियर

गुलाटी साहब बहुत काबिल हैं और उन्हों ने हिन्दुस्तान के केस को मजबूती के साथ पेश किया लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार को लोगों को यह बताना चाहिये कि हम भी इस नहरी पानी के मामले में उतने ही इन्टरेस्टेड है जितना कि पाकिस्तान । अगर पाकिस्तान का बेस्ट इंजीनियर और उस के बेस्ट ब्रेन्स नहरी कान्फ्रेंसेज में शिरकत करते हैं तो हिन्दुस्तान को भी उसी ढंग से इस मसले को सीरियसली लेना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई फैसला न हो और हमारे लोग यह शिकायत न कर सकें कि ऐसा इसलिये हो गया चूंकि हमारी नुमायन्दगी कमजोर थी । इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमें उसी लेविल पर बातचीत करनी चाहिये जिस लेविल पर कि पाकिस्तान करता है । अगर वह मिनिस्ट्रियल लेविल पर बातचीत करता है तो हमें मिनिस्ट्रियल लेविल पर बातचीत करनी चाहिये और सेक्रेटरी लेविल पर अगर वह करे तो हम भी उसी लेविल पर करनी चाहिये । बस मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं ।

16 hrs.

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) जनाब चेयरमैन मैं उन तमाम समझौतों की तवारीख में नहीं जाना चाहता जिन में पिछले स्पीकर्स जा चुके हैं । मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह बताना चाहता हूं कि मेरा सूबा पंजाब इस बारे में क्या सोचता है । यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि वहां के लोग कभी किसी एक मसले पर एक राय नहीं हो पाते लेकिन जहां तक कि नहरी पानी के झगड़े का सवाल है तमाम पंजाबी लोग चाहे वे किसी मजहब के हों, चाहे किसी कास्ट के हों और चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हों, कम से कम इस बारे में वे एक ही तरह से सोचते हैं और वह यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहरों के मामले में पंजाब को बुरी तरह से लैट डाउन किया है ।

•

यह जो भाखड़ा डैम बनाया जा रहा है यह जो भाखड़ा की स्कीम है यह मुत्तहिदा पंजाब की स्कीम थी । मुत्तहिदा पंजाब में बारबार बहसें हुईं । यह अपने दौलताना साहब नहीं थे बल्कि इन के वालिद मोहतरम अहमद यार खां दौलताना उस वक्त मौजूद थे । शौकत हयात नहीं थे बल्कि उन के वालिद मोहतरम सिकन्दर हयात खां मौजूद थे । यह नौजवान मिस्टर ममदोत नहीं थे बल्कि उन के वालिद मोहतरम नवाब ममदोत उस वक्त होते थे जोकि बड़े बुजुर्ग थे । मेरी उन के साथ बड़ी लम्बी एसोसियेशन रही है । मुझे वह हिस्सा बड़ा प्यारा लगता है जिस को कि अब पाकिस्तान कहते हैं । वहां पर भी हमारे भाई लोग रहते हैं । पाकिस्तान के साथ मेरी एप्रोच नफरत पर मबनी नहीं है । वहां पर मेरे भाई रहते हैं और उन से मेरा खून का रिश्ता है जोकि एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है । यह मेरी एप्रोच है और कम्यनिस्ट पार्टी की यह एप्रोच है । सीधी सी बात यह है कि उन्हों ने अपना घर अलग कर लिया है और हम ने अपना घर अलग कर लिया । हमारे सामने सीधी बात यह है कि जब पानी की हमारे यहां कमी है तब हम दूसरे मुल्क को पानी कैसे दे सकते हैं और मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि When Punjab was a united province the feeling was that in Eastern Punjab irrigation was not a developed thing and East Punjab was to be developed with united fund जब पानी की हमारे यहां खुद कमी है तब हम दूसरे मुल्क का कैसे दे सकते हैं । और यह तो वही बात हुई कि मां गुड़गुले दान करे और घर में गुड़ नहीं । मेरे बुजुर्ग मोहतरीम चौधरी छाटूराम ९ जनवरी १९४५ को

[श्री प्र० सिंह० दौलता]

भगवान को प्यारे हुए । ८ जनवरी की शाम को उन्हो ने इंजीनियरों को बुलाया और फाइल मंगवा कर भाखरा डैम पर दस्तखत किये और दस्तखत करने के बाद आराम से लेट गये और कहा कि अब हे भगवान बेशक उठा लो और ९ जनवरी को वह प्यारे हो गये । उस वक्त तमाम मुतहिदा पंजाब के अन्दर यह माग हुई थी कि ईस्ट पंजाब यानी अम्बाला डिवीजन के इरिगेशन को डेवलप करने के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाना चाहिये ताकि दरियाओ का पानी ईस्टर्न पंजाब के लिये बाध बाध कर जमा किया जाय । लेकिन पंजाब का पार्टीशन हुआ । यह पंजाब की बदकिस्मती थी कि उसका पार्टीशन हुआ । इसकी वजह यह थी कि पंजाब वाले किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हाई कमाड में नही थे । पंजाब का पार्टीशन करते वक्त वहा के लोगो की तकलीफ का किसी ने अन्दाजा नही लगाया और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान वालो ने उसको आपस मे बाट लिया । यह तो सन् १९४७ की बात हुई । उसके बाद हम देखते हे कि पंजाब के बारे मे आम एप्रोच यह है कि यह झगडालू सूबा है । लेकिन मै कहता हू कि यह बहुत भले आदमियो का सूबा है ।

यह जो ईस्टर्न पंजाब का नहरो का झगडा है उसको मै समझने मे कासिर हू कि यह चीज क्या है ? आप देखे कि पंजाब का किसान इस के बारे में क्या सोचता है । एक किसान ने मुझ से पूछा कि यह नहर का क्या मसला है ? कही ऐसा तो नही है कि हिन्दुस्तान वालो ने हमारे पानी को पाकिस्तान के पास गिरवी रख दिया है । मै कहता हू कि यह एक सिंपिल सी बात है । दोनों सावरिन मुल्क है । हर एक के अपने अपने दरिया है । तुम अपने दरियाओ का पानी लो हम अपने दरियाओ का पानी लें । इस सिलसिले में एक चीज का रेफरेंस दिया जाता है । पाकिस्तान वाले कहते है कि पाकिस्तान को तो हिस्टारिक सप्लाई आब वाटर मिलनी चाहिये । वह हिस्ट्री की दलील देते है । मुझे सन् '४७ के पहले की किताबों की याद आती है । एक किताब डा० राजेन्द्र प्रसाद की लिखी हुई है और दूसरी डा० अम्बेडकर की । दोनो मास्टर पीसेज है लेकिन दोनों ने बुनियादी तौर पर यह वार्निंग दी है कि भाइयो हिस्टरी ने हिन्दुस्तान को एक रखा है, हिस्टरी से लडाई न लड़ो । हिस्टरी ने मुल्क को इस तरह से जोडा है कि अगर मुल्क डिवाइड हुआ तो बड़ी भारी तकलीफ होगी । लेकिन इस बुनियादी बात को ठोकर मार दी गयी और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया । अब कहा जाता है कि हमको हिस्टारिक रीजन्स पर वाटर सप्लाई मिलनी चाहिये । मै कहता हू कि हिस्टरी की वह कोई दलील न दे क्योंकि हिस्टरी को तो उन्होने ठुकरा दिया और मै समझता हू कि दुनिया में उस तकलीफ की मिसाल नही मिलेगी जो कि पंजाब को हिस्टरी में ठोकर मारने की वजह से मिली । तो मै यह अर्ज करना चाहता हू कि दोनो सावरिन स्टेट्स है और दोनो के अपने अपने दरिया है । इसमें झगडा क्या हो सकता है ।

जहा तक डेवेलपमेंट का सवाल है मै यह बतलाना चाहता हू कि पानी की कमी की वजह से क्या हाल हो सकता है यह आपने १८ तारीख को देख लिया जब कि दिल्ली के लोगो को पानी नही मिला । मुझे वह चीज देख कर खुशी हुई क्योंकि यहा के हुक्मरा लोगो को भी तो पता चला कि पानी न मिले तो क्या तकलीफ होती है । हमारे यहा झज्जर और रिवाडी तहसीलो में पानी का यह हाल है कि एक एक घड़ा पानी लेने के लिये लोगो को सवाईस सवाईस मील इंजनो के पास जाना पड़ता है । वहा पानी की बड़ी

तक़लीफ़ है । पीने का पानी नहीं मिलता है । वहां का पानी खारा है । वहां पर लोग जोहड़ों में बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको काम में लाते रहते हैं । जोहड़ सूख जाते हैं तो वहां पानी नहीं मिल सकता । जब तक वहां की ज़मीन पर नहर का पानी नहीं आवेगा तब तक पानी की तक़लीफ़ दूर नहीं हो सकती । गुलाटी साहब की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन जिन इंजीनियरों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा है कि भाखरा डैम से गुड़गावा को एक घूंट पानी नहीं मिल सकता । रोहतक को एक डाप पानी नहीं मिलेगा, महेन्द्रगढ़ के उरले हिस्से को एक घूट पानी नहीं मिलेगा, परले हिस्से को कुछ मिलेगा । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् '४५ में सर छोटूराम ने पानी के लिये दस्तखत किये थे और उस वक्त की वहां की गवर्नमेंट भी कहती थी कि इन इलाकों को पानी मिलना चाहिये । आज हमारी हिन्दुस्तान की अपनी गवर्नमेंट है लेकिन इस हिस्से को पानी नहीं मिल रहा है । मैं तो कहता हूं कि पंजाब के लिये कोई रिगार्ड ही नहीं है । एक तो यह वजह है कि पंजाब में कोई बड़े आदमी जैसे सर छोटूराम, लाला लाजपत राय वगैरह थे इस वक्त नहीं हैं । हमारी कोई बात बतलाने वाला नहीं है । इससे पहले जब कि पार्टीशन नहीं हुआ था, सर सिकन्दर यह चीज़ हमें देने के लिये तैयार थे, बुजुर्ग दौलताना साहब इसके लिये तैयार थे जो कि इन दौलताना साहब के बाप थे । लेकिन इन नौजवानों के साथ समझौता कर लिया है और हमारी तक़लीफ़ों का लिहाज़ नहीं रखा गया । मेरे ये दिली जज़बात हैं । यह पानी का मामला है । मैं ने राड़ेवाला साहब के साथ इस फसल के ज़माने में अपने इलाक़े का दौरा किया है और देखा है कि पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है और हमारी फसलें सूख रही हैं । ईस्ट पंजाब के अम्बाला डिवीजन की फसलें सूख गयीं उनको पानी नहीं मिला और पाकिस्तान को पानी जा रहा था, और उसके बावजूद पाकिस्तान वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ।

मुझ से एक इंजीनियर साहब ने कहा था कि जब तक सिरसा ब्रांच को भाखरा ब्रांच से नहीं जोड़ा जायेगा । अम्बाला के उरले हिस्से को पानी नहीं मिल सकता और सर्दियों में अगर पाकिस्तान को पानी दिया गया तो अम्बाला तो क्या, पटियाला डिवीजन और जालंधर डिवीजन तक को पानी नहीं मिल सकेगा । जहां तक अम्बाला डिवीजन का ताल्लुक है उसको तो एक घूट पानी नहीं मिलेगा जब तक कि सिरसा ब्रांच की नहर के लिये पानी न दिया जाये और वह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान की सप्लाई बन्द न हो । तो मैं अर्ज करता हूं कि वास्तविक तमाम पंजाब के लोगों की है कि यह झगड़ा तै हो । मैं आपके सामने पंजाब के किसानों के छोटे दुकानदारों के जज़बात पेश कर रहा हूं ।

आज पंजाब का मसला यह समझा जाता है कि यह मिनिस्टर बने या वह मिनिस्टर बने । लेकिन पंजाब का यह मसला नहीं है । पंजाब का मसला यह है कि पंजाब के जो तीन इलाके दिल्ली में लगे हुए हैं आप उनको पानी दें । वहां का पानी का मसला सब से बड़ा मसला है । मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन अपोजीशन में मैं पंजाब का मेम्बर हूं । मेरे भाई जो उस तरफ हैं उनको पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र है । अपने मुल्क के किसानों को उतनी फिक्र नहीं । मैं पंजाब के किसानों के जज़बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज पंजाब के किसान कितनी परेशानी में है । वे आज गवर्नमेंट आफ इंडिया के बारे में यह सोचते हैं कि वह हमारा पानी पाकिस्तान को दे रही है । यह पानी देना जल्द बन्द होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईस्ट पंजाब के लोग उस पानी पर बरसना देंगे जो पाकिस्तान को जा रहा है और फिर आप कहेंगे कि अपोजीशन वाले सिचुएशन का एक्सप्लाइट करते हैं । मैं तो चाहता था कि जो हालत

[श्री प्र० सिं० दोलता]

यहां पर १७ और १८ तारीख को रही वह कम से कम एक हफ्ते रहती तो शायद यहां के हुक्मरां को पता लगता कि पानी के बगैर क्या तकलीफ होती है । हमारी यह तकलीफ उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान का पानी बन्द नहीं होता ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, Sir, in view of the fact that the two Prime Ministers, the Prime Minister of Pakistan and the Prime Minister of India are meeting, I would not like to say anything which will render the situation more difficult than it is already.

But, Sir, the speech of Mr. Desai, who was our High Commissioner in Pakistan for some time, has been an eye-opener for some of us, and I believe that so long as the bureaucracy of Pakistan continues to have the mentality which it has now, so long as the newspapers of Pakistan continue to fulminate against India as they are doing now, and so long as some of the leaders of Pakistan like Mumtaz Daultana go on saying that this canal water issue is a issue fit for jehad, I do not know how we are going to solve this problem.

Sir, I speak from the context of my own constituency, a rice producing area, a sugarcane producing area. I tell you, this canal water dispute is acting like a blight to harm the hopes and aspirations of the cultivators of that district and also other districts of Punjab. The peasants of my district and also other districts in Punjab are being denied that regular supply of water which is their due. There are small feeder channels and those feeder channels do not get the water which is needed for their farms and fields. I have visited them, and I have put this question to the authorities there. They say: "We have to supply data to Pakistan, and we have to tell them that we are not overdrawing the water". At the same time, where new channels are needed in order that more food may be produced, in order that more crops may be grown, those channels are not done and those channels are not given water. Why? In the name of supplying data to Pakistan. I ask you, Sir, what data is Pakistan giving us? In the statement that Hafiz Sahib has placed in our hands we are given that data. They are not giving us any data.

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): We are giving both data and water.

Shri D. C. Sharma: I will come to that also.

What I am saying is, we are giving them data and that data is working detrimentally for the interests of the farmers of Punjab. I do not want to go into the question of drinking water My Communist friend, a very worthy friend of mine—he also says that he is one of my old students, I am very proud of it—raised an irrelevant issue, the issue of drinking water. We are not discussing about drinking water at this time. We are discussing about water which is needed for irrigating our fields, which is needed for feeding the millions of inhabitants in India. That water is denied to the people.

It is being denied because our Government does not pursue—I will choose my words very carefully—a firm, dignified, sensible and good-neighbouring policy. Why? I will explain these words. It is because our Government is always trying to go out of its way to feel friendly. I would say, we should feel friendly, but we cannot feel friendly towards any country at the expense of our own countrymen.

I want to tell the hon. Minister that there is a lot of discontent amongst the people of Punjab on account of the canal water issue. I would request

him to issue a White Paper on this subject That White Paper should be broadcast not only among the Members of Parliament and the journalists of India, but that paper should be broadcast among all the inhabitants of India and also, especially, among the inhabitants of Punjab, because, I may tell you, our good neighbourly policy is not only being misunderstood and misrepresented in Pakistan, but it is also being misunderstood among the people of Punjab What a wonderful policy we have! This policy is finding favour neither with our countrymen nor with the countrymen of Pakitan They are blaming us, and our own countrymen are blaming us I would, therefore request the hon Minister that he should do something to allay the fears and set at rest the misgivings of the peasants of Punjab

Sir, one hon Member said that we have been doing this work as a part-time job I thoroughly disagree with him We have taken this issue very seriously, and whoever has handled this issue has done it with the utmost conviction, with the utmost industry and the utmost technical knowledge He referred to one engineer, I feel there may be other engineers also I may tell you, Sir we owe a debt of gratitude to these persons who have been fighting on our behalf So far as these people are concerned, they have fought gallantly, nobly, and well, and we are proud of them I do not think we have taken up this issue as part-time issue, we have tried to be as knowledgeable about this issue as anyone can be

Sir, it is not only the issue of supply of water which faces Punjab, the Punjab that we have got now This Punjab minus canals minus adeqate lands plus an ever increasing population has got to be made into a flourishing State, and the rivers of the Punjab are the life-blood of Punjab They are not only the life-blood of Punjab, they are the life-blood of India, because Punjab is called the granary of India If you starve Punjab of water, you starve the whole of India of water If you deny Punjab of that water supply, you are practically putting back the clock so far as the Grow More Food Campaign is concerned

Therefore, I would submit very respectfully that we should call a halt somewhere Let the people of Pakistan say that if we do not supply water they will call it an aggression Let us accept this fact, and let there be no going beyond 1962 My friend said that some dispute about canal has been going on between two countries for 80 years God forbid that we should also have that target before us Therefore, I would say that we should stick to 1962 and we should not

An Hon Member: 1959

Shri D. C. Sharma. I think it is 1962 I do not want to dabble in dates, because somebody is there to question you if you quote any figures Therefore, let the present arrangements continue till 1962 and not a day beyond that If we take our stand on that, I think there will be peace so far as this part of the Punjab is concerned

One thing more They have linked up this issue with storage tanks, link canals and all that, and they want exorbitant sums of money from India so that they can keep this thing going I would also request the hon Minister as other Members, that he should see to it that we are not going to temporise on this issue of the link canals and storage reservoirs We are not going to say that we would come to terms with them on these issues and give them some money for building them They want money from us It is we who should get some money from them for building our canals and for other things, and for making water sufficient for our lands I do not think that we should yield to them in that matter

Far be it from me to say anything which should embitter or spoil our relations with Pakistan I want Pakistan and India to be friendly countries

[Shri D. C. Sharma]

but I also want that we should have friendship with honour, friendship with dignity, friendship by preserving the sovereign nature of our country and by preserving the sovereignty of the 36 crores of Indians who inhabit this country.

Shri Harish Chandra Mathur: All the hon. Members who have spoken, belonging as they do to different political parties, have spoken with one voice. They have spoken not only with one voice, but with the same depth of feeling and force on this issue, and it was only natural because this is a very vital and important matter which concerns us not only on the political or economic front which is of an ordinary nature. It as a matter of fact, concerns the most important problems which are facing the country today.

What is Problem No. 1 of the country today, the problem over which there is so much feeling? You saw only yesterday there was such an uproar, and that uproar was about the food problem. Problem No. 1 before the country today is the question of food supplies, and it is in this context that I wish that this Government tackles this issue and understands the urge and the feeling of the entire country.

I have gone through all the documents. My hon friend, the hon Mover of this motion had taken great pains and labour and he has put before the House all the various documents and had traced the complete history, but to me it appears that this question, though it has been unnecessarily complicated, bungled and bogged, is absolutely simple. And this simple matter was, as a matter of fact, quite clearly stated as early as 1948 in that agreement. Today if there is any agreement which subsists between the two countries, it is the 1948 agreement. There is no other agreement at which we have arrived so far. In the absence of any other agreement I want to ask: what are the reasons why we do not stick to that agreement, an agreement which had been signed by the representatives of both the countries, an agreement which was absolutely reasonable and just? Why is it that we are now forgetting that agreement and unnecessarily entering into an endless controversy and discussion costing this country and causing uncertainty to this country? I feel there is absolutely no justification for that.

This question, I again wish to emphasize, should be examined in this context. I hope the hon. Minister has read today's *Hindustan Times*. If he has read it, he would find what is happening in the State of Bikaner today. Thousands of cattle have died, hundreds and thousands of people are facing starvation. It is this Bikaner which would have been today a most highly irrigated place, a place which would have not only improved its own condition but which would have, as a matter of fact, catered not only to the State of Rajasthan but to a major part of this country. While today we are faced with starvation, while today we are faced with water scarcity, while today thousands of our cattle are dying, we are tackling this most vital and important matter in a way which does not satisfy any one in this country.

When I looked at this question, I just asked myself: what has prompted our Government to give an undertaking that we will go on with the present arrangement till 1962? I can anticipate the answer from the Government They will say that we will not be ready with our canals before 1962, and we will possibly not be in a position to take the water from these rivers. In the first place I ask another question of them: why is it that we will not be ready before 1962? This is a matter of such vital importance, why is it that it was not given its due priority? Apart from that, is it not a fact that even at present we are not able to give the necessary water supply to the areas which can draw the water? Is it not a fact that we are starving some of our areas?

The statement which has been laid on the Table of the House very clearly indicates that Pakistan made a complaint that we were not sticking to any agreement, that we were not giving the supply of water to them. I am not aware of the agreement about which they are talking. Which is that agreement to which we are not sticking? The agreement according to which the supply was being made expired in 1957. Pakistan would not enter into any new agreement, Pakistan would not give you data, and yet India feels itself bound not only to give the necessary data, not only to give all the water that comes through these rivers, but they give this at the cost of our own territory by starving our own canals and certain sections of our canals go dry and do not get water.

What is the justification for it? At least, the Government owes a fair explanation to the people of this country. And this happens when Pakistan has stopped making all payments, even the undisputed payments. The undisputed payments, I think, are about Rs. 27 lakhs or more which have not been paid; from quarter to quarter they are falling into arrears, and yet we are continuing the supply of water The undisputed arrears have gone up to the tune of a crore of rupees I wish to put it to the hon. Minister that these undisputed arrears and the disputed arrears will never be paid to India until and unless we are a little more realistic in our policies. I am sure that if Pakistan knows that the water supply would be stopped from tomorrow, the undisputed arrears as well as the disputed arrears will be paid to this country. I have not the least doubt.

Is there any reason for us not to take a realistic attitude in the matter? I do not understand. I can appreciate that we should have a gentlemanly, generous, elder-brotherly, attitude towards Pakistan, but we should not behave in a manner that we encourage Pakistan to get more and more unreasonable. And it is entirely because of our attitude, this soft attitude, which is indefensible, that Pakistan has become more and more unreasonable, and it has created more and more problems and is responsible for their withholding payments. Pakistan was paying at least the undisputed amounts right till 1957 or 1956. They stopped paying it afterwards, because they know the manner in which we are acting and their attitude is such that they can afford to take all the water. Pakistan also paid the disputed amounts till 1950 in the bank. Why have they stopped it afterwards? What action have the Government of India taken? At least the people of this country are entitled to know the reasons for this, after allowing all this latitude and being as gentlemanly as we could.

Today I am really very happy to know that the Prime Minister of Pakistan has spoken in a little more reasonable tone. This 1948 agreement which was being disputed, ignored and not accepted by Pakistan, was brought before the Pakistan Legislative Assembly I am sure, that as promises by the hon. Prime Minister of Pakistan, he must have distributed photostat copies of that document to all members of the Assembly, so that they may understand that they cannot afford to take that attitude. If we want to come to a real and practical settlement, I wish the Government of India to give a clear notice to the Pakistan Government that "we want to be helpful to you. We have been helpful to you; we have been overgenerous to you and still we want to help you. But these disputed and undisputed amounts should be paid, as they have been paid in the past by a particular date, six months or whatever it may be." If they are not paid by that date, then in national interest, the water must be stopped, because if we go on like this, by 1962, by which time Pakistan will not care for our water, there would be no way of realising these arrears.

We have got some experience in the past. On so many other grounds, huge amounts due from Pakistan are not being paid. But now this is the only

[Shri Harish Chandra Mathur]

way of realising these arrears, which are accepted by them.

I will only add a word. This question should not be viewed as a question of Rajasthan or Punjab; I may stress that. Rajasthan is already self sufficient in food and Rajasthan will have more food than it requires. This Rajasthan Canal is an absolutely all-India question. It is going to solve all-India difficulties. In that context, unless this is given highest priority, all our future plans will founder on the rock of food scarcity, if we do not take good care of our schemes and are more generous to our neighbours, with whom we want the best and the most friendly relations. We want to be very helpful, but we should also see that our generosity is not abused and they are not encouraged to be unreasonable.

Shri A. C. Guha (Barasat): My hon friend, Shri Raghunath Singh, has given a complete factual picture of the problem, and I do not want to enter into those aspects. But there are one or two other matters to which the attention of the Government must be drawn.

I think only recently the Chief Minister of West Pakistan or some other responsible Minister stated that the 1948 agreement was signed under duress. If that is the attitude of the Government, how can there be any amicable solution of this problem, through mutual understanding? For the last 10 years, this problem has baffled the International Bank and technical experts starting from Lilienthal, who may be considered to be an expert of international repute in this matter. The Indus rivers pass through India and Pakistan only. But there are other international rivers which traverse through about half a dozen countries, like Danube. Starting from Germany, it passes through Austria, Hungary, Czechoslovakia and Yugoslavia, then forming a boundary between Bulgaria and Rumania, finally falling into the Black Sea through Rumania. The question of that river, the distribution of water and other things, was settled internationally through a commission and there was no difficulty about it. Similarly the Nile river. It is also an international river, and a very important river for Sudan and Egypt. The question of distribution of water of that river, I think, has not created any deadlock so long. It also passes through more than three or four countries. It and its distributaries pass through countries like Kenya, Tanganyika and Ethiopia and many other countries besides Sudan and Egypt. So, I cannot understand why the Government of India has not been firm in this matter to settle the question of the Indus water.

The feelings in this House and perhaps, in the country, is that the other State is taking advantage of the goodness or the weakness of our Government. There can be no question of any bellicose attitude being adopted by this country. We want that India and Pakistan should live in friendly relations. Geographically, we cannot afford to have inimical relation... We must live as friends. But that friendship cannot be purchased by showing weakness. That friendship can be attained only by showing some definite and firm steps on certain issues.

In all financial matters we have been having discussions and conferences with Pakistan for the last ten years and I think their number by now might have approached 100. But we have not been able to reach any agreement on any of them. There may be some paper agreements; but nothing has come out of these agreements on any of the issues. My hon. friend, Shri Mathur, has just now referred to arrears. Even undisputed arrears are not being paid. I think the Government should be firm in this matter. If necessary, we may appear for some time to be somewhat niggardly and hard in this matter Otherwise, it will never be possible for this Government to realise our dues from the Pakistan Government, as our experiences for the last ten years have shown.

Another point I would like to mention here is this. Practically all the rivers of northern India, due to partition, have become international rivers. Brahmaputra is like that and Ganges is also like that. So, if we do not show any firmness in the question of the solution of the Indus water distribution, I cannot visualize what may be the position as regards the distribution of water of the Ganges and of the Brahmaputra and their tributaries. Sir, you yourself know the position of the Brahmaputra and its tributaries. You can very well realise that if Pakistan takes up the difficult attitude, and our Government shows some amount of weakness or so called goodnes, as they have been showing in the case of the Indus river, it will create great difficulties in the whole of the eastern side of India

These are the points I would like to state and I hope the Government will stick to some definite policy If they have given the date of 1962 as the target date, I would not like them to change that date But, in the mean time, they should take some steps to realise our arrears, our dues That should be realised Otherwise, it would not be possible for this Government to realise the arrears at any time This date in 1962 should not be extended on any account There should be a firm and determined declaration that this is the last date and beyond that date there would not be any further extension So, after that date Pakistan may fend for herself and we also would manage whatever we can with our own canals That should be a firm date and there should not be any further extension That is all what I have got to say

सिंचाई और बिजली मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) जनाब चेयरमैन साहब, मैं मेम्बरान का बहुत ही आभारी और मश्कूर हूं कि उन्होंने हमारे इस देश के एक ऐसे बड़े मसले पर, जिस का ताल्लुक हिन्दुस्तान के लाखों आदमियों की जिन्दगी से है बहुत रोशनी डाली, जिस का मुझे सुनने का मौका मिला।

जहां तक इन बातों का ताल्लुक है जो कही गई, उन से पहले एक बात जो मेरे खयाल में इस मसले में हटी हुई थी वह यहां कही गई और जो इस से पहले मेरे इल्म में नहीं थी। इसलिये मैं उन माननीय मेम्बर साहबान का खिदमत में जिन्होंने कि रोहतक हिसार वगैरह की तरफ की पानी की स्केअर्सिटी का तजकिरा किया है, जनाब के जरिये से गुजारिश करना हूं कि अगर वह प्राइवेट तौर पर इस में ज्यादा रोशनी इस मसले पर डालेंगे तो शायद गवर्नमेंट इस मामले की तरफ ज्यादा तवज्जह करेगी।

मैं ने कैनाल वाटर डिस्प्यूट के इस मसले पर जो तकरीरें सुनीं उन से मुझे महसूस हुआ कि हमारे इस मुल्क के नुमायंदों के जजबात इस मामले में क्या हैं। मैं यह अर्ज नहीं करता कि मैं किसी भी हैसियत से यह कह सकता हूं कि जो उन के जजबात हैं वे वेजा हैं। मैं नहीं अर्ज कर सकता। वाकई हर मुल्क के रहने वालों के जजबात अपने मुल्क के फायदे और अपने मुल्क के भाइयों की जरूरतों के लिहाज से ऐसे ही हो सकते हैं जैसे जजबात का इजहार इस जगह किया गया। लेकिन शायद इस बात का खयाल नहीं रक्खा कि इस मामले के ऊपर आज जो मुबाहसा हो रहा है वह दस साल के बाद हो रहा है। अब तक दस साल गुजर चुके हैं इस मसले को चलते हुए और हमारे दर्म्यान और दुनिया के अन्दर यह इतने दिनों से कायम है, और बहुत कुछ विचार इस मसले के मुताल्लिक दुनिया के सामने किया गया। बहुत सी बातें की गईं। आज अमली तौर पर कहां तक यह मुमकिन होगा कि हम उन सब बातों को, जो इस वक्त तक हो चुकी हैं, इग्नोर करें, उन की तरफ से निगाह हटा कर यकलख्त कोई पालिसी अख्तियार कर लें जिस से कि इस किस्म के नतीजे मुरत्तब हों, जिन नतीजों

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

को खुद हमारा दिल भी न चाहता हो ? जिनकी कि निस्बत मैं थोड़ी सी गुजारिश भी करूंगा। तो मैं समझता हूं कि उस रोशनी में अगर इस मामले को देखा जाये तो शायद इतनी सख्त राय न कायम हो जिस की कि निस्बत मैं कोई शिकायत नहीं करता कि वह राय क्यों कायम हुई। लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर पूरी हकीकत को सामने रक्खा जाये तो शायद उसके अन्दर इतनी सख्त नहीं होगी। मसलन् एक बात मैं अर्ज करूं। अब यह तो मेरे लिये मुश्किल होगा कि मैं सभी बातें जो कि यहां पर फरमाई गई हैं उनके मुताल्लिक तफसीली तौर पर कुछ अर्ज कर सकूं क्योंकि वक्त की तंगी है। अलबत्ता उन में से जिस जिस की निस्बत मैं ऐसा समझूंगा कि उनको इस हाउस के सामने रख देना जरूरी है, उनके मुताल्लिक मैं अर्ज कर दूंगा।

एक बात यह फरमाई गई कि आज जो पानी पाकिस्तान को दिया जाता है अपने यहां से सालाना हर फसल के ऊपर वह किस मुआहिदे के मुताबिक है ? उसका यहां एक सवाल हुआ और उसका जवाब दिया गया और उसको वह मन्त्री मैं पढ़ दूंगा लेकिन मैं इस तौर पर जवाब देना चाहता हूं कि फर्ज कीजिये मुआहिदा नहीं हुआ और इस सिलसिले में कानून और इंटरनेशनल ला का भी जिक्र हुआ। मैं ने मान लिया कि इंटरनेशनल ला का भी तकाजा नहीं है और जो मुल्क का हमारा कानून है उसका भी तकाजा नहीं है, लेकिन एक बात मैं उस वक्त इस हाउस में नहीं थी लेकिन मेरे दिमाग में वह मौजूद है, मुझ को किताब याद है वह पढ़ी हुई है और मैं ने उसको इस तौर पर समझा कि वह इस हाउस के कानफरेंस और इस हाउस की पालिसिस को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिये कही गई थी और उसमें यह कहा गया था कि हम पानी पाकिस्तान को इसलिये नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत का हमें कोई लिहाज है बल्कि हम पाकिस्तान को पानी इसलिये देते हैं कि जो लाखों आदमी उस पानी के जरिये से आज अपनी रोजी कमा खा रहे हैं और जिन्दा हैं उनके ऊपर यकलख्त कोई मुसीबत न आ जाये। यह ह्युमैनेटेरियन प्वाइंट आफ व्यू है, इंसानी हमदर्दी का मामला है जिसकी कि निस्बत मैं यह कह सकता हूं कि आज दुनिया के सामने हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के रवैय्ये को नहीं देखते हैं

Shri Goray: What happens to the famine-stricken areas on this side?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यहां के जो आदमी हैं उन में और उधर जो हमारे लोग रहते हैं उनमें क्या फर्क है ? आखिर जब पाकिस्तान नहीं बना था तो वे भी तो यहां के और लोगों की तरह पानी पा रहे थे और पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान की कनाल्स बनी तब भी वे पानी पा रहे थे और अब भी पानी पाते हैं लेकिन अब वह बिलकुल उससे महरूम हो जायेंगे और जिस वक्त तक उनके लिये कोई दूसरा इन्तजाम नहीं होगा उस वक्त तक वे पानी से बिल्कुल महरूम हो जायेंगे और उस वक्त तक उनको कुछ नहीं मिलेगा।

जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है पाकिस्तान ने वाकई लिंक कनाल्स बनाई हैं और उनको जो अब पानी दिया जाता है, जितना लिंक कैनाल्स में पानी मिल सकता है उतने रकबे का उसमें से काट कर पानी दिया जाता है। आज यही हो रहा है और यही तरीका जारी रहेगा जब तक कि यह मामला इस तरीके से चलता है। मगर अब सवाल यह है कि जो मैं समझा तकरीरों के खुलासे में वह यह है कि चूंकि पाकिस्तान की वह बातें हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वह शिकायतें हैं उसकी वजह से पानी बन्द कर दो। मैं

जानता नहीं कि मैं किसी वक्त अपने जजबात के तहत किसी बात को कह दूं लेकिन अगर ठंडे दिल से उसको सोचने बैठूंगा तो किस नतीजे पर मैं पहुंचूंगा। यह मैं जानता नहीं। मैं समझता हूं कि इस ऐवान के मेम्बरान अगर इस बात को सोचेंगे और मेरे उन भाई ने जिन्होंने कि इस मजमून को इन्ट्रोडिउस किया, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमें को उन भाइयों को जी कि हमारे भाई हैं और जिनका और हमारा गोश्त और खून एक है, वे हमारे हैं और हम उनके हैं, उनको हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी है। मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर में यह बात कही और और इस हकीकत को तसलीम किया। अब अगर आज इस हकीकत को तसलीम किया जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई शख्स यह मशविरा नहीं दे सकता है कि इस तरह से बूटली और कूएनी उन आदमियों के साथ कार्यवाही की जाये और उनको उस पानी से महरूम कर दिया जाये। I do not say anything in defence of Pakistan. जो मुआहिदे की शर्तें हैं उनको तो पूरा करें। अब अगर पाकिस्तान को न समझ लिया जाये कि पाकिस्तान मुआहिदे की किसी चीज को एक हिस्से को भी नहीं मानता, किसी पर अमल नहीं करता और कोई काम ठीक नहीं करता तब आप क्या मशविरा देते हैं? क्या हम मुआहिदे की शरायत को न माने? सन् १९६२ तक तो हमें उनको पानी देना ही है.....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली): यह एटीच्यूड अगर पाकिस्तान का दस साल से अब तक रहा है तो वह सन् १९६२ तक यानी तीन साल और बना रह सकता है और उस वक्त भी यही सवाल पेश होगा।

एक माननीय सदस्य: जब तक वहां की सरकार बदल जायेगी और जनता की सरकार बन जायेगी।

श्री अचित राम (पटियाला) पानी आप भले ही दीजिये लेकिन उसके साथ ही साथ उन से पैसा भी मांगिये।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: उनकी पानी की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है और वह बढ़नी चली जायेगी और हम इस बात की कोशिश में हैं कि उनको इसका रिएलाइजेशन आये और वह इस बात को समझें, हमारे जरिये से नहीं तो औरों के जरिये समझायें और उनके ऊपर इस तरह से एनफ्लुएंस डाले कि वे इस मसले को ठीक तौर से समझ कर के जो माकूल तरीका इस मसले के फैसला करने का हो सकता है उस तरीके को अख्तियार करें, यह कोशिश हमारी है...

श्री अचित राम: जरा उस एनफ्लुएंस का जिक्र कर दें जो कि आप उन पर डाल रहे हैं?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: ताकि जो हमारा असर होता हो वह भी खत्म हो जाये। इसका नतीजा इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई तरकीब कर रहा हूं या कोई असर डाल रहा हूं और अगर मैं उस को एक्सपोज करता चला जाऊं और दुनिया को हकीकत मालूम हो जाये तो उस हालत में मेरी वह कोशिश और एनफ्लुएंस बेकार हो जायेगा।

श्री अचित राम: कैसी खुफिया बात है। खुफिया बात को रहने दीजिये जो बेखुफिया बात हो उसको बता दीजिये।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: बात यह है कि सन् १९४७ से अब तक कुछ वक्त एग्रीमेंट्स के होने में और उसके बाद कुछ वक्त वर्ल्ड बैंक से गुफ्तगू होने में गुजरा और गुजर रहा है लेकिन उसी के साथ इतनी बात जरूर है कि जहां तक वाटर सप्लाई का ताल्लुक है यह खुद उसी प्वाइंट पर नहीं है जहां पर कि सन् १९४७ में थी। सप्लाई के ऐतबार

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से वह आगे बढ़ गई है और जितनी वाटर की सप्लाई आपको आज पाकिस्तान को देनी है, उससे ज्यादा देनी नहीं होगी और वह बराबर घटती जा रही है। यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि यह चीज बिलकुल ऐसी नहीं है कि उससे हम बिलकुल मायूस हो जायें। जहां तक किसी फैसले के मामले का ताल्लुक है उस मामले की निस्बत जो कुछ मैं ने यहां तकरीरों में सुना उससे भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस हाउस के मुअज्जि मेम्बरों की राय यह है कि जितना भी मुमकिन हो इस मामले को बाहमी समझौते से तय किया जाये। यह मेम्बरान तसलीम करेंगे कि गवर्नमेंट इस बात पर की बराबर कोशिश करती रही है कि किसी तरीके से यह मामला हल हो जाये। लेकिन मैं और मेरे छोटे भाई जिसके कि मेरे साथ आपस के ताल्लुकात हैं, अगर उन में किसी किस्म का खुदा न ख्वास्ता एख्तलाफ हो और मैं उसको राहरास्त पर लाना चाहूं और वह राहरास्त पर न आये तो क्या मैं सीना तान कर और तलवार ले कर उसके मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा ? यह जरूर है कि गवर्नमेंट इस मामले मे गाफिल नही रही है और उसकी अब भी कोशिश है कि किसी तरह यह मामला शांति और आपसी बरतचीत से तय हो जाये और वह छोटा भाई ठीक एटीच्यूड अख्तियार कर के सही रास्ते पर आ जाये।

एक बात यह इरशाद फरमायी गयी कि गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि हम १९६२ तक इंतिजार करते हैं। इसके मानी साफ है कि हमको तो अपनी लिमिट बता देनी है और जो तकरीरें हुई उनसे मेरे नजदीक यही नतीजा निकलता है कि गवर्नमेंट को यह ऐटीट्यूड ले लेनी चाहिये थी जो कि उसने अब ली है। हम ने अब दुनिया के सामने अपनी यह लिमिट रख दी है और बतला दिया है कि हमारी सब्र की इन्तिहां का यह मुकाम है। हम ने यह बतला दिया है कि जो कुछ करना हो इस अरसे में कर लो।

شری اے ایم طارق (جموں اور کشمیر): - لیکن ہمارے صبر کا پیمانہ تو کبھی لبریز ہی نہیں ہوتا -

[**Shri A. M. Tariq** (Jammu and Kashmir): But our patience is never exhausted.]

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज करूं कि जो आला खयाल लोग होते हैं उनका सब्र का प्याला कभी लबरेज नहीं होता।

Shri Nath Pai (Rajapur): I am sorry to interrupt, but may I point out to the hon. Minister a very small thing? He should either address you or us. He is trying to convince his own party which will uphold him in any case.

Mr. Chairman: I was just about to point out that he should look to the front and address the Chair; he will then be better audible to the whole House

Shri Goray: May I make another suggestion? Some specific points have been raised in this discussion, and we shall be very grateful to know what explanation Government have to offer on those specific points.

Mr. Chairman: He can mention them, so that the hon. Minister can answer.

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जहां तक बैंक के इंटरवेंशन का ताल्लुक है उस के निस्बत शायद मुझ को कुछ कहने की जरूरत तो नही थी लेकिन अभी एक बात कही गयी उस की बिना पर मुझ को उस के बारे में कुछ कहना पड रहा है। बैंक वालो को न पाकिस्तान ने इनवाइट किया और न हिन्दुस्तान वालो ने इनवाइट किया, बल्कि अभी यह बात चर्चा में आयी है कि एक साहब ने, जो कि अमरीका के थे, अपना एक मजमून किसी रसाले में छपवाया जिस में उन्होंने कहा कि यहां हिन्दुस्तान में और ऐशिया के

इस हिस्से में एक नया कोरिया बन रहा है। उस कोरिया के किस्से को पढ़ने के बाद वर्ल्ड बैंक ने खुद पूछा कि क्या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान इस के लिये तैयार हैं कि उन से कोई बात इस मामले को तय करने की की जाये तो वह उस को सुनें। इस पर पाकिस्तान ने भी बताया कि हम तैयार हैं और यही जवाब हिन्दुस्तान ने भी दिया। इस पर बैंक ने इस मामले को टेक अप किया और उन्हों ने उसे अभी भी टेक अप कर रखा है, और आप को अखबारों से यह भी मालूम हुआ होगा कि उन को इस मामले में कुछ डिसएपाइंटमेंट भी हुआ, लेकिन बावजूद उस डिसएपवाइन्टमेंट के वे उस मामले के धागे को बराबर जारी रखे हुए हैं और उस को छोड़ नहीं रहे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो इस मामले का फैसला आपस के तस्फिये से हो जाये। चुनाचे मैंने उस रोज अर्ज किया था कि जो प्लान पाकिस्तान ने इस वक्त बना कर उन को दिया है वह हम को दिया गया है ताकि हम उस को एग्जामिन करें। उस के बाद जो मीटिंग्स वगैरह होने वाली हैं उनमें मैंने यह तवक्को जाहिर की है कि शायद कुछ फैसला हो जाये।

एक बात और है। पाकिस्तान को रुपया देने की बात कही गयी। उस के मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि इस मामले में, अभी तक हिन्दुस्तान का कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम को आया रुपया देना है या नहीं और अगर देना है तो कितना देना है। किसी रकम का कमिटमेंट हिन्दुस्तान की तरफ से नहीं हुआ है और अभी उस का मौका भी नहीं आया कि हम से यह कहा गया हो कि हम को इस मामले में आखिरी तौर पर क्या तै करना है। रुपया तो वह होगा जो पाकिस्तान को उन नहरों के लियेचाहिये कि जो वह उस पानी को छोड़ने के लिये बनायेगा जो कि वह अभी हिन्दुस्तान से ले रहा है। इस के मुताल्लिक यह कहा जाता है कि प्रिंसिपल यह है कि अगर हिन्दुस्तान पाकिस्तान से वह पानी छुड़ाना चाहता है तो वह उस खर्च को अदा करे जो उतना पानी पैदा करने के वास्ते उन को करना पड़ेगा। यह एक बात कही जाती है। इस उसूल को दुनिया के लोग भी मान रहे हैं और यहां भी उस को माना जाता है, तो उस के मुताबिक शायद हम को भी कुछ तै करना हो लेकिन उस रकम के मुताल्लिक अभी तक कुछ तै नहीं किया गया है।

अब एक बात और मैं जनाब वाला की खिदमत में अर्ज करूंगा। वह यह कि जो तकरीरें कुछ साहिबान मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं उनको सुन कर अगर हम अपनी तबीयतों के ऊपर असर ला कर अपनी राय कायम करें। तो मेरे ख्याल में कोई इस को सही नहीं मानेगा। यह भी कोई तरीका है कि मसलन दौलताना साहब ने कुछ इरशाद फरमाया, या किसी और साहब ने कुछ इरशाद फरमाया, और उन के उस फरमान की बिना पर हम अपनी तबीयत में असर ले कर के अपने उस तरीके को जो तरीका कि हम ने इस वक्त तक इस मामले को फैसला करने का अख्तियार कर रखा है छोड़ दें, और उस के बजाय कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर लें।

और एक बात मैं अर्ज करूं कि जितनी बातें यहां कही गयी उन के बारे में कहा गया कि ये शिकायतें हैं। लेकिन मेरे सामने कोई कास्ट्रक्टिव प्रोपोजल नहीं आया कि हम इस मामले में और क्या तरीका अख्तियार करें। आम तौर पर यह कहा गया कि साहब पानी बन्द कर दो। इस के अलावा और कोई तरीका किसी के पास नहीं है। अगर कोई तरीका है तो वह पानी के बन्द करने का है। पानी को बंद करें या न करें यह तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन अगर उस के सिवा कोई दूसरा तरीका किसी के ख्याल में था तो वह हमारी सामने नहीं आया। न किसी ने यह कहा कि हम इस मामले में क्या पालिसी अख्तियार करें।

एक बात डिसप्यूटेड और अनडिसप्यूटेड पेमेंट्स के बारे में कही गयी। इसके मुताल्लिक

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। डिसप्यूटेड क्या है। जो बारी दुआब कैनाल है उस के बारे में यह ठहरा हुआ है कि पाकिस्तान उस की जो बुक वैल्यू या कैपिटल वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट अदा करे और मेनाटनन्स कास्ट अदा करे। जहां तक कैपिटल वैल्यू का ताल्लुक है उस के बारे में यह डिसप्यूट है कि उस की कितनी कीमत लगाई जाये। इस नहर को बने हुए सौ बरस हो गये। उस वक्त आज के मुकाबले में बहुत कम खर्चा हुआ होगा। जो नहरे कि ५०, ६०, ७० या ८० साल पहले बनायी गयी हैं उन नहरों का इस नहर से मुकाबला किया जाय तो वह नहीं चलेगा। हमारी तरफ से यह बात कही गयी कि बारिदुआब कैनाल की कीमत बुक वैल्यू की चौगुनी मानी जाये। पाकस्तान वाले कहते हैं कि नहीं दुगनी मानी जाय। यह डिसप्यूट है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर १९५० तक जो वह बैंक में रुपय जमा करते रहे वह किस बेसिस पर जमा करते रहे ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम वह डिपोजिट यों हुआ। वह किसी बेसिस पर नहीं था। वह तो यह तै हुआ था कि एक फिकस्ड एमाउन्ट जो हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बतला देंगे वह रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जायगा। लिहाजा वह एमाउन्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया वह १९५० तक जमा किया गया। वह किसी खास बेसिस पर नहीं दिया गया। मगर उस में दो चीजें डिसपूटिड हैं। एक पाइंट तो यह डिसप्यूटिड है कि सीनियरेज लिया जाये या नहीं। सीनियरेज क्या है, उस की मिसाल मैं आप को दूं। भावलपुर स्टेट में नहर निकली, उस से जो पानी वे लेते थे, उस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट सीनियरेज लेती थी। जैसे और स्टेट्स थीं, जो कि अब खत्म हो गई हैं, वैसे ही यह भी स्टेट थी। हम ने कहा कि उस के ऊपर सीनियरेज मिलना चाहिये। वह उस को डिसप्यूट करते हैं। ये दो प्वाइंट्स डिसप्यटिड हैं—एक तो सीनियरेज के मुताल्लिक और दूसरा अप्परबारी दोआब कैनाल के मुताल्लिक

श्री नाथ पाई : कभी कभी ऐसा लगता है कि सभा में न होकर मंत्री महाशय और श्री अचिन्त राम के बीच बेड के नीचे बहस हो रही है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मुझ को तो चेयर के सामने बोलने की वाकफियत है। मैं इस वक्त यू नहीं बोल रहा हूं कि मैं ने कहीं और, बदकिस्मती से कहिये या खुश-किस्मती से, यह देखा नहीं है कि इस तरीके से लोग अपनी तरफ को मुतवज्जह करें। मुझ को कहीं कोई आवाज देगा, तो नेचुरली मेरा ख्याल और दिमाग उस तरफ जायेगा और बगैर मेरे उस तरफ फिरे मेरा चेहरा उस तरफ को फिर जाता है, लेकिन यह बगैर इन्टेन्शन के होता है—अन इन्टेन्शनली होता है। चूंकि मुझे इस से पहले कभी इस तरह का इत्तिफाक नहीं हुआ, इसलिये मैं उस तरफ खिंच गया हूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने आप को ट्रेन कर लूंगा कि बावजूद इधर उधर की कोशिश के चेयर की ही तरफ देखूं।

जैसा कि मैं ने अर्ज किया है मैं मैम्बरान का बहुत मशकूर हूं। उन्हों ने हम को—गवर्नमेंट को—बहुत सबक दिया है, बहुत अच्छा मशविरा दिया। हम चाहते हैं कि खुदा उन के मशविरे पर अमल करने की हम को तौफीक दे और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे भाई पाकिस्तान से जिस तरीके से भी हो, एक मुनासिब और उम्दा फैसला हो जाय और यह सब किस्सा खत्म हो जाये।

सरदार इकबाल सिंह मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन की लिंक चैनल—सुलेमान की बल्लोकी लिंक चैनल और बल्लवाला बादिया लिंक चैनल बन चुकी है, जहां से वे अप्पर बारी दोआब के पानी की कमी अपने ढंग से

पूरी कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर क्या वजह है कि सरदियों में फीरोजपुर हैडवर्क्स से इस्लाम, पंचनद और सुलेमान की लिंक के लिये पानी दिया जाता है, जब कि हमारी नहरों में उतने दिन, या कुछ दिन के लिये बन्दिश रहती हैं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैंने यह अर्ज किया था कि अब जो हम पाकिस्तान को पानी देते हैं, वह उस पानी को काट कर देते हैं, जो कि उन के यहां अपनी नहरों के जरिये से उन को मिलने लगा है और मिल सकता है ।

Mr. Chairman: The House will now stand adjourned.

Shri Braj Raj Singh: Shri Raghunath Singh has to reply.

Mr. Chairman: He has no right to reply.

17.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 5th September, 1958.